



असंशोधित

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

15 फरवरी, 2019

घोडश विधान-सभा

15 फरवरी, 2019 ई०

द्वादश सत्र

शुक्रवार, तिथि: -----

26 माघ, 1940 (शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय - 11.00 बजे पूर्वाह्न)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया ।)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है । माननीय सदस्यगण, इससे पहले कि प्रश्नकाल शुरू हो, मैं इस सदन में एक संवेदनापूर्ण प्रस्ताव

(व्यवधान)

आप ही की भावना इसमें है । माननीय सदस्यगण इससे पहले कि प्रश्नकाल शुरू हो, मैं इस सदन में एक संवेदनापूर्ण प्रस्ताव आपकी सहमति हेतु उपस्थापित करना चाहता हूँ । कल दिनांक 14 फरवरी, 2019 को

(व्यवधान)

माननीय सदस्यगण, कल दिनांक 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के

(व्यवधान)

अध्यक्ष: शांति-शांति । भाई वीरेन्द्र जी, कृपया सहयोग कीजिये । माननीय सदस्यगण, कृपया शांति बनाये रखिये ।

माननीय सदस्यगण, आप सबों का ध्यान एक गंभीर विषय की ओर आकृष्ट कर रहा हूँ, कृपया शांति बनाये रखियेगा ।

कल दिनांक 14 फरवरी, 2019 को जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में आतंकवादियों के हमले में सी०आर०पी०एफ० के 40 से भी अधिक जवान शहीद हो गये । इन जवानों में बिहार के भी दो सपूत शहीद हुए हैं । हम सभी इस लोमहर्षक घटना से मर्माहत हैं । यह सभा इस कायराना हमले की कठोरतम शब्दों में भर्त्सना करती है और हमले में शहीद सभी जवानों के प्रति भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती है । यह हमला सी०आर०पी०एफ० के जवानों पर नहीं बल्कि देश की अखंडता एवं एकजुटता पर हमला है । ऐसी राष्ट्रीय आपदा के समय में यह सदन और संपूर्ण बिहारवासी एकजुटता एवं ढृढ़ता से राष्ट्रीय भावना के साथ हैं तथा आशा करते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु दी गयी इन शहीदों की आहूति व्यर्थ नहीं जायगी । हम सभी सदस्यगण शहीद जवानों के शोकाकुल परिजनों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट करते हैं और ईश्वर से इस दारुण दुख सहन करने की उन्हें शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं ।

माननीय सदस्यगण, अब हमलोग एक मिनट तक मौन खड़े होकर दिवंगत शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि हेतु प्रार्थना करेंगे ।

(एक मिनट का मौन)

अध्यक्षः कृपया बैठ जाइये ।

श्री भाई वीरेन्द्रः अध्यक्ष महोदय, अब सदन को आज स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः महोदय, सदन को आज स्थगित कर दीजिये और आज वाला बिजनेस को कल ले लीजिये । कल शनिवार का दिन है, बंद भी है, इसलिए अभी कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुला लीजिये और इसपर निर्णय ले लीजिये । आज सदन को स्थगित कीजिये । यह अच्छा संदेश जायेगा ।

अध्यक्षः तो अभी सदन को 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित कर देते हैं ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकीः ठीक है । कर दिया जाय ।

अध्यक्षः अब सदन की कार्यवाही 2.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-2/सत्येन्द्र/15-2-19

(अन्तराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्षः अब सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

श्री ललित कुमार यादवः अध्यक्ष महोदय, हमलोगों का सुझाव है कि आतंकी हमले में जो शहीद हुए हैं बी0एस0एफ0और सी0आर0पी0एफ0 के जवान तो हमलोगों का कहना है कि ये सदन आज स्थगित कर दिया जाय ।

अध्यक्षः अब कहाँ ।

श्री ललित कुमार यादवः और इस जवान को महोदय सेना के समान शहीद का भी दर्जा नहीं मिलता है ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय..

अध्यक्षः इस पर मौन रख चुके हैं, अब मौन रखने के बाद क्या सुन लें बतलाईए ।

श्री अवधेश कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है अध्यक्ष महोदय, आज पूरा देश मर्माहत है, इस तरह की घटना को हमलोग पक्ष हो या विपक्ष हो उससे मतलब नहीं है, इस घटना से सारे लोग मर्माहत हैं । आपने सुबह में कंडोलेंस किया, हमलोग आपकी बात को मानकर हमलोग भी आपके साथ हैं, मगर इतनी बड़ा हादसा अभी तक देखने को हमलोगों को नहीं मिला है अध्यक्ष महोदय, तो हमलोगों का आग्रह है कि आज कम से कम सदन उन नौजवानों को, उन सैनिकों को और देश को बिहार एक संदेश दे कि बिहार के लोग देश की एकता और अखंडता में एक साथ एकजुट हैं और आज बिहार विधान-सभा को इस इश्यू पर हमलोग बंद करते हैं, आपका इश्यू फायरेंसियल इश्यू कोई महत्वपूर्ण इश्यू नहीं है अध्यक्ष महोदय, वह कल भी आप कर सकते हैं, कल हाउस बंद है आप कल उसको बुलाकर कार्यमंत्रणा में कर लीजिये, सभी विपक्ष के लोग आपके साथ हैं मगर आज देश का आंसू बह रहा है, हमारी बेटी बेवा हो रही है, हमारी मां बहन रो रही है, उस पर आप जो आदेश देंगे वह सर्वमान्य हैं मगर इस पर विचार करें ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य, अवधेश जी और ललित जी, ये बातें प्रथम पाली में भी आयी थीं। जिस बात को आप अभी बोल रहे हैं कि देश और प्रदेश के सारे लोग एकजुट हैं । अभी बोलना तो अनावश्यक इसलिए है कि आप ऑलरेडी पहले ही उस संबंध में प्रस्ताव पारित कर चुके हैं तो जिसका प्रस्ताव आप कर चुके हैं उसी बात को फिर से बोलने की तो कोई आवश्यकता नहीं है । दूसरी बात अवधेश जी, प्रस्ताव पारित हुआ है, उसी के सम्मान में आप खड़े हुए हैं तो कितनी देर तक सदन स्थगित रहता है, इससे क्या मतलब संवेदना का पैमाना होता है और सबसे बड़ी बात है, बैठिये महबूब जी, इन सब संवेदनशील विषयों को अनावश्यक विवाद में मत डालिये, इससे किसी का

भला नहीं हो रहा है, सीधी बात है और सबने एक राय से, जब हमलोग श्रद्धांजलि में एक मिनट मौन होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए खड़े हुए, उनके शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना के लिए खड़े हुए, पूरे प्रदेश और बिहारवासियों की इस समय में, राष्ट्रीय विपति के समय में पूरे देश की भावना के साथ हमने एकजुटता का प्रदर्शन कर दिया है तो देश की एकता अखंडता के लिए अब इस मुद्दे को क्या फिर कल भी उठा देने से ज्यादा मजबूती मिल जायेगी, अनावश्यक इसको विवाद का विषय मत बनाईए ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: अनावश्यक विवाद का विषय मत बनाईए । प्रभारी मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ।

सभा मेज पर कागजात का रखा जाना

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619 (ए)(2) के तहत बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम का वर्ष 2012-13 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के सभी माननीय सदस्यगण सदन से बहिर्गमन कर गये)

श्री श्रवण कुमार, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, आपकी तरफ से शहीदों के लिए आज यहां पर शोक किया गया । एक मिनट का मौन रखकर के सभी माननीय सदस्यों ने श्रद्धांजलि दी महोदय और उनके शोकाकुल परिवार को, आत्मा को शांति मिले इसके लिए आपने एक मिनट का मौन धारण किया लेकिन ये लोग राजनीति करना चाहते हैं महोदय और राजनीति कर के सारे मामले को इधर उधर करना चाहते हैं, महोदय तो मैं समझता हूँ कि शहीदों के प्रति जो सम्मान है आपका, जो सदन का सम्मान है जो बिहार की जनता का सम्मान है माननीय मुख्यमंत्री और सरकार का जो सम्मान है, आपने निश्चित रूप से उन शहीदों के प्रति सम्मान दिया है और मैं समझता हूँ इनको इस विषय पर राजनीति नहीं करना चाहिए ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आसन इस बात से सहमत है कि प्रथम पाली में यह एक आम राय सभी दलों के माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गयी, भावनाओं से तय हुआ था कि हमलोग श्रद्धांजलि उनके शहादत पर अर्पित कर के एक मिनट का मौन कर के प्रथम पाली में सदन स्थगित कर देंगे । मुझे आश्चर्य है कि सदन स्थगित होने के बाद भी जो माननीय सदस्य अभी बात कर रहे थे उसमें से अधिकांश मेरे पास आये थे, सारे लोगों से बात हुई थी और सब लोग लगभग सहमत थे इस बात से, सदन स्थगित होने का मतलब सीधा स्थगित होना होता है, सम्मान का सूचक होता है । अब कितनी देर के

लिए स्थगित हुआ, ये तो कोई पैमाना नहीं होता, अब कल भी स्थगित कर दें तो और ज्यादा सम्मान हो जायेगा, यह कोई पैमाने की बात होती नहीं है। इस शोक की घड़ी में जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, उन शहीद सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए या उनके शोक संतप्त परिवारों को दुख सहन करने की शक्ति देने के लिए जब हम भगवान से प्रार्थना कर के एक मिनट मौन रखकर के चले गये सब सहमत होकर के, अब फिर से उस बात को उठाना या इस पर वाद विवाद प्रारम्भ कर देना या इस पर हम यह सोचते हैं, हम ये सोचते हैं, जब सारे सदन ने मिलकर सोचा और आप भी उसमें भागी थे, आपकी भी उसमें सहभागिता थी, आपकी भी उसमें सहमति थी और आप भी चाहते थे कि सदन आज स्थगित हो थोड़ी देर के लिए तो फिर इस बात को उठाना, ये न कोई अच्छी परम्परा है और न इससे कोई शहीदों के प्रति हम अपना सम्मान बढ़ा रहे हैं। इसलिए ऐसी चीजों से बचना चाहिए और इतने संवेदनशील मुद्दों को इस तरीके से अनावश्यक या तो वाद विवाद या विचारों के आदान प्रदान का विषय नहीं बनाना चाहिए।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, अब वित्तीय कार्य लिये जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए लेखानुदान विवरणी पर विचार विमर्श किया जाना है इसके लिए आज एक दिन का ही समय निर्धारित है। लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव पर वाद विवाद के लिए तीन घंटे का समय उपलब्ध है। विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संघ्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है तथा इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा :

राष्ट्रीय जनता दल	- 59 मिनट
जनता दल(यू०)	- 52 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-39 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	- 20 मिनट
सी०पी०आई(एम०एल०)	-02 मिनट
लोक जनशक्ति पार्टी	- 02 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	- 01 मिनट
राष्ट्रीय लोक समता पार्टी	- 02 मिनट
निर्दलीय	- 03 मिनट

अध्यक्ष: प्रभारी मंत्री वित्त विभाग, अपनी मांग प्रस्तुत करें।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“ लेखानुदान वर्ष 2019-20 की अनुसूची के स्तम्भ 8 से 11 में अंकित अधिक से अधिक 77338,52,96,000 (सतहत्तर हजार तीन सौ अड़तीस करोड़ बावन लाख

छियानवे हजार) रूपये मात्र की रकम का लेखानुदान उक्त अनुसूची के स्तम्भ में प्रविष्ट अनुसार मांग शीर्षक के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर खर्च करने के लिए स्वीकृत किया जाय।”

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है।

अध्यक्ष: इस मांग पर माननीय सदस्य श्री रामदेव राय से संशोधन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें सारे अनुदान की राशि में से 10 रु०० घटाने का प्रस्ताव है, जो व्यापक है और इसपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं। अतएव माननीय सदस्य श्री रामदेव राय, अपना संशोधन प्रस्तुत करें।

श्री रामदेव राय - अनुपस्थित

संशोधन प्रस्ताव मूव नहीं हुआ। इसलिए मूल प्रस्ताव पर विमर्श होगा।

श्री वशिष्ठ सिंह।

टर्न-3/मधुप/15.02.2019

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदय, विनियोग विधेयक के पक्ष में बोलने के लिए हमको मौका जो आपने दिया है, मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ।

महोदय, निश्चित तौर पर कल इस देश के सैनिकों की जो हत्या हुई है, उसका निन्दा प्रस्ताव हमलोगों ने सदन में पास किया और प्रथम पाली को स्थगित भी किया गया और सभी देशवासियों की संवेदना भी है।

महोदय, इन सब मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और मैं समझता हूँ कि एक साथ मिलकर अगर इस तरह के मुद्दे पर आदमी बात-विचार करके कुछ निर्णय पर पहुँचे तो अच्छा होगा। हमलोगों की सरकार, देश की सरकार मंथन कर रही है कि इस तरह की घटना को कैसे रोका जाय और उसका पूरा जोरदार तरीके से बीच-बीच में मुकाबला भी किया जाए। सर्जिकल स्ट्राइक भी किया गया, कई तरह की कार्रवाई की। लेकिन जो लोग वाक-आऊट करके गए तो उनके नेता ने जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो क्या बोला था? अब तो ये लोग चले गए। राजनीति कर रहे हैं। हमलोगों के नेता राजनीति नहीं करते हैं, काम में विश्वास करते हैं। क्या नहीं इनलोगों ने बोला था? सर्जिकल स्ट्राइक पर बोलकर हिन्दुस्तान की सेना को अपमानित करने का काम किया था। उसका लोग प्रुफ मॉग रहे थे इसलिए इस तरह की बात करके ओछी राजनीति नहीं होनी चाहिए। सदन का जो काम है, उसमें हाथ बैटाकर सहयोग करके सदन को चलाना चाहिए, बिहार का विकास हो, जनहित में काम हो लेकिन इनको जनहित से कुछ लेना-देना नहीं है।

महोदय, हमारे बिहार सरकार के माननीय मुखिया परम आदरणीय नीतीश बाबू और उप मुख्यमंत्री आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार चौतरफा विकास कर रहा है। महोदय, सात निश्चय कोई मामूली बात नहीं है। निश्चय का मतलब संकल्प और उस संकल्प को धरती पर उतार देना यह अपने-आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बात है।

शिक्षा के सवाल पर क्या था आज से 15 साल पहले? 2005 के दशक को भी हमलोग याद करते हैं और आज को भी देखते हैं तो कितना फर्क दिखता है। 12.5 प्रतिशत से ज्यादा बच्चे बाहर सड़क पर घूमा करते थे। आज स्थिति यह है कि मात्र 1 परसेंट बच्चे बाहर रह गए हैं, सारे बच्चे विद्यालय में जाने का काम करते हैं। इतना ही नहीं महोदय, मजदूर की बेटी, गरीब की बेटी, दलित-शोषित की बेटी जब बड़ी हो जाती थी, सयानी हो जाती थी, कपड़ा के अभाव में 7-8 क्लास में पढ़ाई करने नहीं जा पाती थी। लोग सोचते थे कि चिट्ठी-पत्री भर हो गई है, अब यहीं से इसकी पढ़ाई को समाप्त करा दिया जाय। जब बिहार में सरकार बनी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की, तो उन्होंने एक सोच डेवलप किया और उन्होंने कहा कि गरीब की बेटी हो, चाहे की अमीर की बेटी हो, दलित की बेटी हो चाहे पिछड़ा की बेटी हो या सर्वर्ण की बेटी हो, बिहार सरकार पोशाक राशि देगी और उसी एक तरह की पोशाक में सभी तरह की बच्चियाँ बैठेंगी और एक साथ बैठकर पढ़ने का काम करेंगी।

महोदय, पहले हाई स्कूल 5 कि0मी0 की दूरी पर, 4 कि0मी0 की दूरी पर, 7 कि0मी0 की दूरी पर हुआ करता था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने साइकिल की राशि देने का काम किया, साइकिल योजना चलाने का काम किया। सिर्फ बड़े-बड़े लोगों के घर में, हाता में बच्चियाँ साइकिल चलाती थीं, मुख्यमंत्री जी की सोच के कारण एक गरीब, एक निर्धन की बेटी, एक मजदूरी करने वाले की बेटी भी साइकिल पर बैठकर हाई स्कूल जाना शुरू की। मैट्रिक में पास करने के सवाल पर 10 हजार रु0 तक का मेधा पुरस्कार देने की योजना सरकार ने बनाई और बच्चियों के हौसले में पंख लग गए। आज बच्चियाँ चाहे मैट्रिक की परीक्षा हो या इन्टर की परीक्षा, आज बिहार टॉपर बन रही हैं। यह हमारी सरकार का विजन है, यह सोच है।

महोदय, ये लोग चले गए, जब हमलोग बोलते हैं कि हमलोगों की सोच में और आपकी सोच में क्या अन्तर है तो ये लोग कूदने लगते हैं। ये वही लोग हैं जिनको शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं है। शिक्षा को चौपट करने पर ये लोग अमादा थे। महोदय, इतना ही नहीं, आज के डेट में बच्चियों के लिए छात्रवृत्ति से लेकर तमाम तरह की व्यवस्था की गई है। महोदय, जो हमारे मध्य विद्यालय थे, उस मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय में परिणत किया गया ताकि हमारे इस राज्य के बच्चे और बच्चियाँ

अच्छी और उच्च शिक्षा ग्रहण करें। 2005 के बाद 2018 तक 5921 उच्च विद्यालय इस राज्य में बनाये गये।

महोदय, इतना ही नहीं, इन्टर तक की पढ़ाई करके हमारे बच्चे एवं बच्चियाँ का रिजल्ट देखा जाता था तो बच्चे अगर इन्टर में 100 पास करते थे तो बी०ए०(ऑनर्स) की स्थिति को देखने से पता चलता था कि मात्र 13 बच्चे ही बी०ए० की पढ़ाई कर पाते थे। 87 परसेंट बच्चे बैंक हो जाते थे। मुख्यमंत्री जी ने इसका सर्वे कराया कि आखिर इसका कारण क्या है कि 87 परसेंट बच्चे बैंक हो जाते हैं, बी०ए० की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं? जबतक बिहार का बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो फिर बिहार का समुचित विकास नहीं हो पायेगा, बिहार की तरक्की नहीं हो पायेगी चाहे वह टेक्निकल पढ़ाई हो, मेडिकल की पढ़ाई हो। मुख्यमंत्री जी द्वारा सर्वे के माध्यम से देखा गया कि गरीब लोग, मजदूर के बच्चे पैसा के अभाव में उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्होंने सात निश्चय के माध्यम से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की शुरूआत की। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने के बाद बिहार के गरीब के बच्चे भी पढ़ाई में, टेक्निकल पढ़ाई में और उच्चस्तरीय पढ़ाई में आज आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, इतना ही नहीं, उसमें एक और व्यवस्था की गई कि जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है, बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है, स्टूडेंट के गार्जियन को जमीन का मॉर्गेज कराकर बैंक के पीछे-पीछे चक्कर काटने की बात नहीं की गई है, केवल जिस बच्चे को पैसा लेना है उसका सर्टिफिकेट जमा होगा और उसके बाद उस बच्चे के इंस्टीच्यूट के खाते में पैसा जायेगा और उससे वह पढ़ाई करेगा। अगर बच्चा पढ़-लिखकर नौकरी में चला गया तो जो निम्नतम ब्याज का जो दर है सरकार का, उसपर अपना पैसा लौटा देगा। अगर वह बच्चा पढ़-लिखकर नौकरी नहीं कर पाया और उसके गार्जियन की आर्थिक स्थिति कमजोर है तो राज्य सरकार उस पैसा को लौटायेगी, भरपाई करेगी, यह व्यवस्था सरकार ने किया है। महोदय, यह अपने-आप में बहुत बड़ी बात है। यह माननीय मुख्यमंत्री के सोच की देन है, उनका विजन है जो इस तरह की व्यवस्था देकर, बिहार के बजट का सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा विभाग पर होता है चूंकि शिक्षा समाज का अनमोल रत्न है, शिक्षा समाज का दर्पण है, जो शिक्षित होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, वही तरक्की करते हैं। इसलिए महोदय, हम सरकार को इस विषय पर धन्यवाद देना चाहते हैं।

महोदय, हम स्वास्थ्य विभाग की बात करना चाहते हैं, आज की सरकार और 2005 की सरकार की अगर तुलना की जाय तो कहीं कुछ दिखाई नहीं देता था स्वास्थ्य विभाग में।
....क्रमशः.....

टर्न-4/आजाद/15.02.2019

..... कमशः

श्री बशिष्ठ सिंह : स्वास्थ्य विभाग में सूई रहता था तो रुई नहीं रहता था और रुई रहता था तो सूई नहीं रहता था । डॉक्टर रहते थे तो कमपाऊन्डर गायब रहते थे और कमपाऊन्डर रहते थे तो डॉक्टर गायब रहते थे । बेड पर कुत्ता सोया हुआ मिलता था

(इस अवसर पर माननीय सभापति(डॉ० रंजू गीता)ने आसन ग्रहण किया)

और आज की स्थिति यह है कि एक नहीं अनेक, गरीब नहीं सम्पन्न किसान भी जाकर के अस्पताल में दवाई करा रहे हैं और सारी दवाईयां मिल रही हैं । महोदया, पी०एम०सी०एच० की स्थिति जर्जर थी, आज पी०एम०सी०एच० में ईलाज के लिए हमलोग क्षेत्र से तमाम जनता आती है और ईलाज कराती है और जहां कोई दिक्कत होता है हमलोग उसको मदद भी करने का काम करते हैं । आज पी०एम०सी०एच० में ५हजार बेड की क्षमता वाला विश्व स्तर पर अस्पताल का निर्माण कराया जा रहा है, इसके लिए भी मैं स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारियों को, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ । आई०जी०आई०एम०एस० में, एन०एम०सी०एच० में ढाई हजार बेड की क्षमता वाला होस्पीटल का निर्माण कराया जा रहा है । आने वाले दिनों में मैं मानता हूँ कि बिहार के लोगों को दिल्ली और देश के बाहर ईलाज कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी समुचित व्यवस्था बिहार में होगी और बिहार में गरीबों का कल्याण और उसका स्वास्थ्य का सुधार बिहार में होगा महोदय । किंडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था की गई है, कैंसर संस्थान की व्यवस्था की गई है । आज कैंसर का ईलाज यहां के गरीब लोग, यहां अपने बिहार में करा रहे हैं, पटना में करा रहे हैं ।

महोदय, तमाम तरह की व्यवस्था सरकार कर रही है । सभापति महोदया, अब हम चलते हैं बिजली विभाग पर । बिजली विभाग 2005 से पहले जिन लोगों को केवल काम से मतलब नहीं, केवल ओछी राजनीति करने में विश्वास रखते हैं और बिहार की जनता को गुमराह करने में विश्वास रखते हैं । जो चले गये, रहते तो बात सामने-सामने होती तो थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता । ये 2005 में पहले 700-800 मेगावाट बिजली की व्यवस्था पूर्ववर्ती सरकार कर रही थी और सोचिए जरा 12 वर्षों में, 13 वर्षों में आज 5000-6000 मेगावाट बिजली की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है और यह बिहार में व्यवस्था हो रही है । आज हमारी सरकार के सात निश्चय में यह भी था कि हर घर को लगातार बिजली देना । पहले के लोग पूछते थे कि ‘ये हो बिजली आईल है ई बेरा, अरे ना भाई कहां से वह तो काले-परसों से बिजली तो नईखे आईल,

यह तो गजब हाल बा इस सरकार के' और आज लोग पूछते हैं कि 'का हो ई तो सुबह से ही बिजलिया जलत ई बल्ब, गईल ना का, ना ई तो सुबह से ही आईल बा, अभी ले बिजली न भागल ह' यह बिहार सरकार की सोच है, यह बिहार सरकार का विकास करने का तरीका है।

महोदय, इतना ही नहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा कि नहर से सिंचाई के लिए पानी तो दे ही रहे हैं, नल से तो पानी दे ही रहे हैं महोदया, हम इतना ही नहीं करेंगे, बिजली से जिस किसान को सिंचाई के लिए पानी चाहिए, मैं उसकी भी व्यवस्था कर रहा हूँ और आज के डेट में इसका लक्ष्य है, 2019 दिसम्बर तक जितना किसान चाहेंगे, उसको बिजली की व्यवस्था दी जा रही है। सिंचाई करने के लिए उनको ट्रांसफर्मर, तार, पोल की व्यवस्था की जा रही है और किसान को चूंकि आज का किसान लघु किसान हो गये हैं। दो बीघे, चार बीघे, पाँच बीघे वाला किसान बच गये हैं, सीमान्त किसानों की संख्या कम हो गई है। अगर छोटा-छोटा प्लॉट पर बिजली की व्यवस्था हो जायेगी जो सरकार की सोच है, अगर बिजली की व्यवस्था हो जायेगी तो किसान जो है, वह केवल गेहूँ, धान का उत्पादन नहीं करेंगे बल्कि उस जगह पर छोटी-छोटी जमीनों पर सब्जी का खेती करेंगे, लहसुन का, पियाज का खेती करेंगे और ज्यादा मुनाफा कमायेंगे, यह बिहार सरकार की सोच है और हमारे किसान सम्पन्न होंगे। हमारे किसान की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने बिजली की व्यवस्था सिंचाई के लिए सरकार कर रही है, पटवन कराने के लिए। महोदया, इतना ही नहीं बिजली विभाग में जितना जरूरत है बिजली की, इस देश में, इस राज्य में जैसे एक शरीर में जो भेन होता है, उस भेन में जो ब्लड का संचार जितना तेजी से होता है, बिहार के विकास के लिए, इस देश के विकास के लिए उतना तेजी से, उतना रफ्तार से बिजली का जब संचार होगा, तब जाकर के बिहार का तरक्की होगा, देश का तरक्की होगा। यह हमारी सरकार की सोच है और सरकार इस पर काम कर रही है।

महोदया, एक से दूसरे को जोड़ने की, एक इलाके से दूसरे इलाके को जोड़ने का जहां तक सवाल है, आज बिहार में तमाम पुलें बनी हैं। कई अन्य नदियों पर मिडिल क्लास की पुल 2124 पुलों का निर्माण हुआ है लेकिन महोदया, 8 महासेतु पर बड़ी-बड़ी पुल बनाने का काम बिहार सरकार ने किया है और 3 महासेतु पर अभी निर्माणाधीन है। अभी बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू ने दाऊदनगर और नासरीगंज के बीच में जो सोन नदी है, उस नदी पर पुल का उद्घाटन करने जा रहे हैं। वही बगल में सोन नदी में सहार और अख्तल के बीच में पुल का निर्माण हुआ है। कहां था महोदया, कहीं था, कहीं नहीं था और आज यह पुल बन रहा है और आने में हमलोगों को सुविधा हो रही है। यही बगल में महोदया, कोईलवर पुल अंग्रेज के जमाने का पुल है, बड़ी कठिनाई होती है, आज सरकार उसमें पुल बनाने में काम लगा दी है।

पुल बन रहा है, पैरलल में पुल बन रहा है, शाहाबाद के लोगों को आने में, जाने में, पटना राजधानी में आने में सुविधा होगी महोदया । यह सरकार की सोच है, विजन है और कुछ लोगों को विकास से कोई लेना-देना नहीं है महोदया, केवल राजनीति करना है, फेस वैल्यू चमकाना है । जिनकी कोई औकात नहीं है, आज विपक्ष के नेता के भूमिका में बैठे हुए हैं, क्या औकात था ? यदि हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से आज वैसे लोग विधायक बन बये और विधायक बनने के बाद तो फिर परिवारवाद का सिलसिला जारी रहा और अब्दुल बारी सिद्धिकी जैसे लोगों को किनारा करके और दो-दो सिनियर नेता उनके सामने बैठते हैं । महोदया, यही नहीं एक दिन माननीय सदस्य विपक्ष के लोग ऊँगली उठा रहे थे, हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू पर, श्रवण बाबू पर, हमारे मुख्य सचेतक पर, क्या ऊँगली उठाइयेगा, वही हाल है, भोजपुरीया कहावत है महोदया, सुपवा हँसे तो हँसे, चलनिया का हँसी । यह भोजपुरी में कहावत है कि सुपवा हँसे तो हँसे, चलनिया का हँसे, चाहे यहां देख लीजिए इस सदन में और चाहे विधान परिषद् के उस सदन में, जो भी पद है, वे लोग अपने पास रखे हुए हैं ।

महोदया, ये लोग अकलियत समाज की वोट की बात करते हैं । एक बार रथ रोकने के बाद जीवन भर एग्रीमेंट करा लिये हैं अकलियत का वोट का, लेकिन अकलियत का कल्याण नहीं हुआ, अगर अकलियत का कल्याण हो रहा है तो बिहार के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कल्याण हो रहा है । इतना मैं बताना चाहता हूँ कि कब्रिस्तान की घेराबंदी कहां हुआ करता था । हमलोग भी पढ़ाई-लिखाई छोड़कर डायरेक्ट राजनीति में आये थे, 20-21 वर्षों से हमलोग भी समाज सेवा में लगे हुए हैं । कहां बनता था, कहां कब्रिस्तान की घेराबंदी हुआ करती थी । आज कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो रही है । महोदया, अलीगढ़ के तर्ज पर यहां यूनिवर्सिटी का काम शुरू हुआ है, मदरसा में शिक्षा का सुदृढ़ीकरण हो रहा है । अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बन रहा है । अल्पसंख्यक को रोजगार करने के लिए ऋण दिया जा रहा है, यह कहां व्यवस्था था ? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस देश में और किसी राज्य में यह क्षमता नहीं है, इतना ताकत नहीं है कि जितना बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, इस देश का कोई राज्य उतना काम नहीं किया है महोदया । मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूँ ।

महोदया, यूनिक चीज, आज विवाद बिहार में चाहे अन्य राज्यों में क्यों होता है, चूँकि जमीन से विवाद ज्यादा है और जमीन का विवाद का कारण है चूँकि दादा के नाम से, बाबा के नाम से जमीन है और उसी पर परिवार बढ़ता गया, खांडगी बंटवारा होता गया, लेकिन उसका सही रूप से कागजी बंटवारा नहीं हो पाया । चूँकि इसपर सरकार का रेवेन्यू ज्यादा था, लोग इसको नहीं करा पा रहे थे । माननीय मुख्यमंत्री जी

उसके झगड़ा के जड़ में गये कि आखिर झगड़ा कहाँ से पैदा हो रहा है तो पता चला कि जमीन से झगड़ा ज्यादा पैदा हो रहा है। उन्होंने 100रु0 में, मात्र 100 रु0 में आप अपने जमीन का बंटवारा करा सकते हैं, यह राज्य सरकार की सोच है और राज्य सरकार ने यह अच्छा काम किया है और बिहार के जमीन विवाद को कम करने का प्रयास किया है।

महोदया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहाँ मुखिया बनते थे, एकल पद पर कोई आरक्षण दिया तो बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश बाबू ने दिया और आज गरीब, दलित का बेटा, महादलित का बेटा, अनुसूचित जाति का बेटा आज मुखिया बन रहे हैं, प्रमुख बन रहे हैं। महोदया, अनुसूचित जाति को 10 लाख रु0 उद्योग विभाग से उद्योग करने के लिए पैसा मिल रहा है

..... क्रमशः

टर्न-5/शंभु/15.02.19

श्री वशिष्ठ सिंह : क्रमशः.....और 50 परसेंट राशि उसमें माफ है और अन्य जो राशि है वह 84 किश्त में देना है महोदया, यह गरीब के उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। महोदया, अन्य कई योजनाएं हैं इसके साथ-साथ हर घर नल का जल हमारे सात निश्चय में है और नल के जल की क्या सोच थी। आप देखी होंगी महोदया कि बड़े-बड़े पदाधिकारी, बड़े-बड़े उद्योगपति के घर में सिंटेक्स लगा हुआ करता था और सिंटेक्स के माध्यम से नल के जल से उनके बाल-बच्चे, परिवार स्नान करते थे और हमारे गांव में रहनेवाले गरीब लोग चापाकल चलाने के लिए मजबूर हुआ करते थे और चापाकल गरीब का गांव में नहीं हुआ करता था। उसको गांव से आधा कि0मी0 दूर, 200 मी0 दूर जाकर हमारी बेटियां, हमारी बहुएं माथा पर तसला में पानी लेकर, बाल्टी में पानी लेकर आती थी। एक बाल्टी से स्नान करती थी और उसी से कपड़ा धोने का काम करती थी। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिहार में समानता की व्यवस्था हम करेंगे, चाहे एक उद्योगपति का बेटा-बेटी हो, चाहे एक मजदूर का बेटा-बेटी हो अगर एक उद्योगपति के घर में नल के जल से उसका परिवार स्नान कर रहा है तो झोपड़ी में रहनेवाली गरीब की बेटी, बहू को भी हम नल का जल देंगे और वह नल के जल से स्नान करेगी। यह व्यवस्था हमारी सरकार ने किया है और काम जारी है, काम पूरा भी होगा। हमारे नेता आदरणीय नीतीश बाबू की जो सोच है और जो उनकी सोच के साथ-साथ उनका विचार है जो किसी चीज का संकल्प लेते हैं तो उसको पूरा करने का काम करते हैं। महोदया, हर घर में नली गली न केवल मुखिया को बल्कि त्रिस्तरीय पंचायत में सबसे निचला इकाई है वार्ड और वार्ड को भी मुख्यमंत्री जी ने जोड़ने का काम किया। वार्ड के सहमति से चयन होता है वार्ड और वार्ड चयन करके हर वार्ड में आज नली गली का काम हो रहा है। कुछ लोग छटपटाये हुए थे पहले लेकिन आज सबलोग मिलजुलकर काम

कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो काम शुरू किया तो लोग सुप्रीम कोर्ट तक गये थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के सोच के साथ दिया और कहा कि सही है। आज नली गली बन रहा है, हर गांव में हर बसावट में जो कहीं न कहीं छूट गया है एकाध परसेंट उस गांव को भी चयनित करके हमारी सरकार बनाने का काम कर रही है। आज के डेट में 1125 किमी⁰ हमारी सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क बनाने का काम किया है। महोदया, इतना ही नहीं, जिस सड़क पर काफी लोड था गाड़ी का उसको पी०डब्लू०डी० अधिग्रहण करने का काम कर रही है। इसलिए महोदया, सरकार की सोच चौतरफा विकास है कि चौतरफा विकास होना चाहिए। महिलाओं के सशक्तिकरण पर महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पंचायती राज संस्थान में, नगर निकाय निर्वाचन के संस्थान में, प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 50 परसेंट आरक्षण हमारी सरकार ने दिया है। सात निश्चय में मुख्यमंत्री जी ने एक बात यह भी कहा था कि हमारी जो बेटियां हैं वह जननी हैं। जो आज की बेटी है वह कल की माँ है। इसलिए उसको पढ़ाना लिखाना उसके अंदर अच्छे संस्कार का निर्माण कराना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है। मुख्यमंत्री जी ने उसको भी पढ़ाने लिखाने का व्यवस्था किया और साथ ही साथ नौकरी में 35 परसेंट आरक्षण देने का काम किया। सात निश्चय में 35 परसेंट का आरक्षण हमारे बिहार की बेटियों को मिला और वह आरक्षण में किसी जाति और धर्म की बात नहीं है। वह आरक्षण सभी वर्गों के लिए दिया गया है। यह हमारी सरकार ने व्यवस्था किया है। उसके माध्यम से आज हमारी बेटियां टॉप कर रही हैं, पढ़ रही हैं। उसके जोश और जुनून में मनोबल बढ़ा है। इसलिए महोदया, हम कहना चाहेंगे पुलिस की बहाली में आज हमारी बच्चियां रूचि ले रही हैं और तैनात होकर के काम कर रही हैं। महिला बटालियन का गठन हुआ। महिला पुलिस थाना का निर्माण हुआ और इतना ही नहीं पुलिस सब इन्सपेक्टर और कॉन्सटेबल में भी 35 परसेंट आरक्षण बिहार की बेटियों को मिला है। यह बिहार सरकार की सोच है। हमारी आधी आबादी हमारे साथ चलेगी तब जाकर के उस क्षेत्र में बिहार का विकास होगा और कल्याण होगा। इसके साथ ही साथ महोदया, हम आपको बताना चाहेंगे जीविका- जीविका के माध्यम से गांव की महिलाएं जो सुबह शाम केवल खाना बनाकर के अपने घर में बैठी रहती थीं, अनावश्यक इधर का बात उधर किया करती थीं, लेकिन आज जीविका के माध्यम से सभी महिलाएं गांव की महिलाएं, गृहणियां जो हैं वह भी मिलजुलकर अपना विकास का काम कर रही हैं। कई तरह से छोटे छोटे लघु उद्योग लगाकर के काम कर रही हैं। इसीलिए 8 लाख 26 हजार स्वयं सहायता समूह का गठन बिहार में हुआ है। यह अपने आप में मिशाल है और 95 लाख 93 हजार परिवार को इससे लाभ मिला है। महोदया, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ -लोक शिकायत अधिकार अधिनियम यह देश का पहला राज्य है बिहार और इस देश के सबसे टॉपर मुख्यमंत्री हैं परम आदरणीय नीतीश बाबू और उनके साथ लक्ष्मण के रूप में काम करनेवाले आदरणीय नेता सुशील कुमार मोदी जी- आज जो लोक

शिकायत अधिकार अधिनियम लाकर के बिहार के गरीबों को जिनका कुछ सुनता नहीं था उसका भी काम आसानी से हो रहा है और 4 लाख से ज्यादा लोगों का मामला निष्पादन हुआ है। इतना ही नहीं इस देश के कोन-कोने से लोग आ रहे हैं और यहां समझ रहे हैं, सीख रहे हैं कि कैसे बिहार में यह कानून लागू हुआ है, क्या इसकी नियमावली है। कई राज्य के लोग आकर के यहां से जानकारी लेकर गये हैं। यह हमारी सरकार की सोच है, हमारे सरकार का विजन है। महोदया, इतना ही नहीं दोनों में अंतर है- हमारे नेता कहते हैं कि बिहार की आम अवाम और बिहार की जो जनता है वही मेरा परिवार है और जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनको बिहार के आम अवाम से कोई मतलब नहीं है। उनका केवल बेटा, बेटी, पत्नी ही उनका परिवार है। दोनों की सोच यही है। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार के नौजवान, बिहार की नवयुवतियां ही हमारी बेटी हैं, लेकिन वे कहते हैं कि नहीं मेरा जो 9 पुत्र हैं वही मेरा बेटा है वही मेरा बेटी है। यही सोच है। इसलिए महोदया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कई संकल्प यात्रा के माध्यम से, विकास यात्रा के माध्यम से कई तरह के माध्यम से गांव में जाते हैं और गांव में घूमते हैं, जनता से डायरेक्ट पूछते हैं। इस देश में आदरणीय नेता नीतीश बाबू को छोड़कर लगातार 10 वर्ष तक किसी नेता ने जनता के दरबार में खड़ा नहीं हुआ है। इतिहास है लगातार 10 वर्ष तक जनता के दरबार में बिहार के मुख्यमंत्री ने खड़ा होकर उनकी समस्या को सुनने का काम किया है। आज लोक शिकायत निवारण कानून बनाकर के उनकी समस्या का हल करा रहे हैं तो दूसरी तरफ महोदया हर सोमवार को लोक संवाद करते हैं और लोक संवाद के माध्यम से उसमें पदाधिकारी को नहीं बुलाया जाता है, उसमें बड़े-बड़े नेताओं को नहीं बुलाया जाता है उसमें आम अवाम और जनता जो इच्छुक है कि हम किसी चीज पर बोलेंगे और बिहार की समस्या में निदान कराने में वह सार्थक होगा उस तरह की जनता को बुलाया जाता है और माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के साथ-साथ सारे विभाग के पदाधिकारी बैठते हैं और उनकी समस्या को, उनके विचार को सुनते हैं, अगर सही होता है तो उसको लागू करने का काम करते हैं। यह बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन है, सोच है।

सभापति(डा०रंजु गीता) : अब आप समाप्त करेंगे माननीय सदस्य।

श्री वशिष्ठ सिंह : महोदया, निश्चित आपके आदेशानुसार हम समाप्त करेंगे और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए चूंकि आपके आदेश का पालन करते हुए महोदया, हमलोग एक किसान हैं और किसान के बेटा है इसलिए अपनी बात को यही कहकर मैं समाप्त करूँगा कि कृषि के क्षेत्र में कृषि रोड मैप बनाकर बिहार के किसानों को अधिक से अधिक विकसित करने का सरकार ने काम किया है। अब इसपर बोलने लगें हमलोग तो लंबा समय लग सकता है। हम शाहबाद जिला से आते हैं, हमारा रोहतास घर हुआ और हमारा इलाका इस राज्य में धान और गेहूं के मामले में सबसे रिच माना जाता है, धान का कटोरा कहा जाता है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी सोन नदी पर जलाशय बनाने जा रहे हैं और जब इन्द्रपुरी जलाशय बन जायेगा तो

केवल रोहतास, कैमूर, बक्सर और शाहाबाद भोजपुर ही नहीं बल्कि औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, गया का दो प्रखंड और पटना का दो प्रखंड लगभग 8 जिला उस पानी से लाभान्वित होगा और जो किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा.....क्रमशः।

टर्न-6/ज्योति/15-02-2019

क्रमशः

श्री वशिष्ठ सिंह : आठों जिला मिलकर पूरे बिहार को अन्न देने का काम करेगा । महोदया, यह व्यवस्था सरकार कर रही है । इसमें अरबों रुपये की लागत लग रही है और सबसे बड़ी बात कहना चाहूंगा कि जिस नक्सली इलाके नौहट्टा से आगे जगन्नाथपुर जहाँ डर से कोई जाता नहीं है, उस इलाके में माननीय मुख्यमंत्री जी गए और जा कर उसका सर्वेक्षण किए । उसमें खुद हमलोगों ने भाग लिया और सर्वधित विभाग के बिजली विभाग और सिंचाई विभाग के प्रधान सचिव के साथ मीटिंग किया ।

सभापति(श्रीमती रंजु गीता) : अब आप समाप्त करें । माननीय सदस्य श्री तार किशोर प्रसाद ।

श्री वशिष्ठ सिंह : इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार पक्ट करते हुए और आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद ।

सभापति (श्रीमती रंजु गीता) : माननीय सदस्य श्री तार किशोर प्रसाद, आपका समय 10 मिनट।

श्री तार किशोर प्रसाद : माननीय सभापति महोदया, आज बिहार के वित्त मंत्री सम्माननीय श्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखानुदान मांग के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । सभापति महोदया, आज प्रथम पाली से ही सदन की तस्वीर को सभी लोग देख रहे हैं । पूरे राज्य की जनता भी देख रही है । कल जो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, उसपर पूरा देश मर्माहत है और उस घटना का राजनीतिक लाभ लेने का प्रयास जिस ढंग से विपक्षी दलों ने सदन के अंदर करने का प्रयास किया, उसकी हम निन्दा करते हैं । आज कटिहार में नेता प्रतिपक्ष का आगमन हुआ और कटिहार में भी नेता, प्रतिपक्ष ने प्रेस के माध्यम से जिस तरीके से इस घटना को रखने का प्रयास किया, उसकी भी निंदा आज इस सदन में हम करते हैं क्योंकि सदन की ओर सदन के सदस्यों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि बिहार कैसे चलेगा, बिहार कैसे आगे बढ़ेगा और यह कहा भी गया है कि जो प्रतिपक्ष है वह सरकार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है लेकिन वह अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सके और स्वाभाविक है कि बिहार जिसतरह से इनलोगों के नेतृत्व में आज से 13 वर्ष पहले जो बिहार की स्थिति थी और जब एन.डी.ए. की सरकार बनी तो उसे बदलने का काम बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और बिहार के वित्त मंत्री उप मुख्यमंत्री श्री सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में बिहार ने विकास के क्षेत्र ने एक अंगड़ाई ली और बिहार के विकास में मुझे लगता है कि आजादी के बाद एक नयी इबारत लिखने का काम इनलोगों ने किया । बिहार इनके कुशल नेतृत्व में वित्त मंत्री के

कुशल प्रबंधन में बिहार ने जिस ऊंचाई को छूने का प्रयास किया और जिस रिपोर्ट की चर्चा हमारे माननीय वित्त मंत्री ने भी किया कि बिहार ने एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है। सभापति महोदया, बिहार का वित्तीय वर्ष 2019-20 का जो बजट आकार दो लाख करोड़ से ज्यादा है और जब 2005 में हम सब जीत कर आए थे उस समय के 2004-05 के बजट का आकार मात्र 26 हजार करोड़ रुपये था स्वाभाविक है कि यह जो एक अंतर है, यह 17 गुणा की बढ़ोत्तरी ऐसे नहीं हुई है। “दिवाली यूं ही नहीं मनी, दिया को रात भर जलना पड़ा है।” नीतीश कुमार जी और सुशील कुमार मोदी के नेतृत्व में बिहार में जीवन के सभी क्षेत्रों में एक बेहतरी करने का प्रयास किया है। बिहार का जो मानव संसाधन है, उस संसाधन का बेहतर इस्तेमाल बिहार के विकास के लिए सूबे के विकास के लिए जो हमारा मानव बल है जो ह्यूमैन रिसोर्सेज है, उसके तथा बिहार की तरकी के लिए उसे कैसे उन्हें संसाधन उपलब्ध करायें, उन्हें कैसे रोजगार उपलब्ध करायें इसके लिए लगातार प्रयास हमारे नेताद्वय ने करने का प्रयास किया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि सात निश्चय योजना हो, चाहे बिहार राज्य फसल सहायता योजना हो, स्वच्छ भारत मीशन शहरी योजना, जीविका, लोहिया स्वच्छता योजना के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन साफ रूप से दिख रहा है। जब हम याद करते हैं 2004-05 के उस पूर्व के काल को जब हम सड़कों पर चल नहीं सकते थे, पगड़ंडी के सहारे पूरा बिहार चल रहा था और आज हम टोला का जो उप टोला वहाँ भी चमचमाती हुई पक्की सड़के दिख रही है। सभापति महोदया, यह जो सड़कों की चमक है यह मात्र सिमेंट, गारा और गिट्टी की सड़क नहीं है। वह सड़क है एन0डी0ए0 सरकार की जनता के प्रति जो प्रतिबद्धता है, जो एन0डी0ए0 सरकार की जो सोच है, वह सोच उस सड़क में दिखती है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो एक गुणात्मक परिवर्तन करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। हमने देखा है कि पटना में जो आई0जी0एम0एस0 स्वास्थ्य संस्थान के रूप में काम कर रहा है। अभी हाल में कैन्सर संस्थान के लिए 100 बेड का संस्थान 138 करोड़ रुपये की लागत से उसका शिलान्यास भी किया गया है। मुजप्फरपुर के श्री कृष्ण महाविद्यालय के परिसर में भी इस तरह के संस्थान के निर्माण करने का शुभारम्भ किया गया है और सबसे बड़ी घोषणा कि बिहार में 11 नये मेडिकल कॉलेज की स्थापना और एक डेन्टल कॉलेज की स्थापना की घोषणा भी हमारी सरकार ने की है। जहाँ बिहार के होनहार नौजवान दूसरे राज्यों में जाकर तकनीकी शिक्षा ग्रहण करते थे। बिहार का पैसा दूसरे राज्यों में खर्च होता था, उसे माननीय मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज सभी जिलों में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। हम धन्यवाद देते हैं कि कटिहार ऐसे पिछड़े जिले में भी इन्होंने कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना करके कटिहार को शैक्षणिक क्षेत्र में एक विशिष्ट पहचान देने

का काम किया है। महिलाओं के सशक्तिकरण के क्षेत्र में क्योंकि वह जो हमारी माताएं और बहने हैं, उनको भी राज्य के विकास में देश के विकास में उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। संविधान ने उन्हें बराबरी का दर्जा भी दिया है और हमारे नेतृत्व ने शिक्षकों की बहाली में 50 प्रतिशत और पुलिस की बहाली में 35 प्रतिशत का आरक्षण हमारी माताओं और बहनों को देकर उन्हें स्वालम्बन के क्षेत्र में उन्हें आत्म बल देने का काम किया है। जीविका के माध्यम से हमारी माताएं और बहनें सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका का जो एक ग्रूप सेल्फ हेल्प ग्रूप है, उसको बनाकर आज वह स्वालम्बन के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हम कटिहार से आते हैं और कटिहार में सदर अस्पताल के परिसर में 300 बेड की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। हम सरकार से भी आग्रह करेंगे कि उस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास किया जाय और हमारे कटिहार की जो मुख्य सड़क है चन्द्रमा चौक, कटिहार से रघुनाथपुर जो राज्य उच्च पथ है उसके चौड़ीकरण का मामला लंबित है उसे भी शीघ्र करवाने का प्रयास करेंगे।

क्रमशः

टर्न-7/15.02.2019/बिपिन

श्री तार किशोर प्रसाद : क्रमशः कटिहार काफी तेजी से विकसित हुआ है। इस नेतृत्व में कटिहार में डॉ० राजेन्द्र प्रसाद पथ में एक फ्लाई ओवर का निर्माण उस क्षेत्र में जो जाम की समस्या है जो आवागमन है उसको दूर करने का एक प्रयास फ्लाई ओवर के साथ किया जा सकता है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम बिहार के मुख्यमंत्री जी को और माननीय उप मुख्यमंत्री जी को जिन्होंने लगातार प्रबंधन के द्वारा इस सरकार को एक नई दिशा में, एक बेहतर दिशा में ले जाने का काम किया है और अंत में कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त करता हूँ -

उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है,
मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है
वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से
वो और थे जो हार गए आसमां से
रख हौसला वह मंजर भी आएगा
प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा
थक कर न बैठें मंजिल के मुसाफिर
मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा।

जय बिहार। बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति (श्रीमती रंजु गीता): माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा ।

(इस अवसर पर माननीय सदस्य श्री रत्नेश सादा अनुपस्थित)

सभापति (श्रीमती रंजु गीता): माननीय सदस्य श्री केदार प्रसाद गुप्ता ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : माननीय सदस्या, आज सदन में लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का जो मुझे मौका दिया गया है, इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और अपने पार्टी के नेतृत्व और कुदूनी क्षेत्र की महान जनता को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं ।

महोदया, आज बिहार के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी और जनप्रिय माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बिहार न्याय के साथ विकास और सबका साथ सबके विकास के लिए कृत संकल्पित है ।

महोदया, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-वित्त मंत्री जी के कुशल नेतृत्व में बिहार के सभी वर्गों को बजट में हिस्सा देने का काम जो किया गया है इसके लिए बिहार की जनता हृदय से माननीय मुख्यमंत्रीजी और उप मुख्यमंत्री जी को आशिर्वाद दे रही है । इस बजट से बिहार की जनता का तकदीर बदलने का मौका मिलेगा ।

माननीय महोदया, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए चार महीनों तथा अप्रैल, मई जून एवं जुलाई, 2019 अवधि के लिए देय अनुदान पारित करने का अनुरोध किया गया है ।

महोदया, लेखानुदान पर निधियों की कुल आवश्यकता 7733852.96 लाख रूपए तक की है जिसमें राजस्व लेखे के अंतर्गत 6205867.45 लाख रूपए पूँजीगत लेखे के अंतर्गत 527983.51लाख रूपए है ।

महोदया, मैं लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । महोदया, सरकार द्वारा इस राशि का खर्च सभी विभागों में विकास कार्य हेतु किया जाएगा ।

महोदया, सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विकास हेतु कृत संकल्पित है । विकसित बिहार के सात निश्चय के तहत गांव या शहर के सभी घरों के नल का जल, शौचालय, गली नाली एवं बिजली की सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है ।

महोदया, खाद्यान्न में पोषण, उपभोक्ता की सेहत और किसानों की आमदनी के लिए सरकार सब्जी की खेती को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है ।

महोदया, सरकार द्वारा पटना में आरब्लॉक-दीघा छः-लेन सड़क, पूर्णिया जमुई, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज, गया में मॉडन केरियर सेंटर, बाल्मीकी टाइगर रिजर्व, मुंगेर, भीम बांध में इको टूरिज्म, मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल और हर प्रखंड में अभी सहायता केंद्र खोलने की दिशा में अग्रसर है ।

महोदया, सरकार इस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक राशि शिक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य, समाज कल्याण, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, ऊर्जा, पी.एच.डी., पंचायती राज, शहरी विकास एवं आवास एवं अन्य पर खर्च करेगी ताकि राज्य का विकास तेजी से हो सके। महोदया, राज्य सरकार 2019-20 में राज्य की 58 जिलों से पटना उच्च न्यायालय तथा राज्य के 62 न्यायालयों के बीच मल्टी विडियो कांफॉर्सिंग सिस्टम से जोड़ने की दिशा में अग्रसर है।

महोदया, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत शुरू की गई हर घर नल की जल योजना के तहत 4095 पंचायतों को 56079 वार्डों में पेयजल की सुविधा मुहैया कराने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। महोदया, राज्य के सभी नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना के तहत शहरी क्षेत्र के हर घर को नल का जल मुहैया कराने का लक्ष्य है। अब तक सभी नगर निकायों के 2379 वार्डों में काम शुरू हो चुका है जिसमें 329 वार्ड में काम पूरा किया जा चुका है तथा 2 लाख 76 हजार 846 घरों को नल का जल उपलब्ध कराया जा चुका है।

महोदया, राज्य के 21,598 वार्ड लौह प्रभावित क्षेत्र में आते हैं जहां पीने के पानी की समस्या है। इनमें से 134 वार्ड में हर घर नल का जल योजना पूरी की जा चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में 13 हजार वार्डों में हर घर नल का जल योजना से पानी पहुँचाने का लक्ष्य है। इसी प्रकार, 2871 फ्लोराइड प्रभावित वार्डों को हर घर नल का जल योजना से जोड़ दिया जाएगा।

महोदया, सरकार प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों तथा पॉलिटेक्निक संस्थानों में इंटरनेट सुविधा प्रदान करेगी। साथ-ही-साथ सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों में वाई-फाई सुविधा प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है।

महोदया, सरकार द्वारा 54 ए.एन.एम. और 23 जी.एन.एम. स्कूल खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त नालंदा में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा स्थापित की जाएगी।

महोदया, सरकार तारेंगना में ऐस्टो टूरिज्म सर्किट का निर्माण कराएगी।

महोदया, सरकार 2019-20 में व्यापक पैमाने पर नियुक्तियां करने जा रही है जिसमें स्वास्थ्य विभाग में 21,571 पुलिस विभाग में साढ़े तेरह हजार, प्रयोगशाला प्रावैधिकी के 1772, फर्मासिस्ट के 345, चालक के 466, आशुलिपिक के 326, स्वच्छता निरीक्षक के 276 पद, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लगभग 32,000 पद, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 581 पशु चिकित्सक, 1392 असैनिक एवं यांत्रिक अभियंता 558, दंत चिकित्सक 295, सहायक प्रोफेसर सम्मिलित है।

महोदया, सरकार ऊर्जा के क्षेत्र में काफी तेजी से कार्य कर रही है। केंद्र एवं राज्य की एन.डी.ए. सरकार प्रत्येक घर में बिजली पहुँचाने का कार्य काफी तीव्र गति से कर रही है। अब तक बिहार के सभी 39073 गांव एक लाख छः हजार दो सौ उनचास

टोलों तथा 32.49 लाख इच्छुक परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन समय-सीमा से दो माह पहले दिया जा चुका है जिसके चलते बिहार सभी घरों तक बिजली पहुँचाने में देश का आठवां राज्य बन गया है ।

महोदया, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत किसानों को कृषि कार्य हेतु विद्युत आपूर्ति के लिए विद्युत उपकरण एवं पृथक फीडरों का निर्माण कराया जा रहा है ।

महोदया, राज्य के 71,672 सर्किट किलोमीटर खराब एवं जर्जर विद्युत तारों को चरणबद्ध तरीके से बदलने का कार्य कर रही है । इसके अतिरिक्त दस हजार प्रिपेड मीटर लगाने के लक्ष्य के विरुद्ध 9100 मीटर लगाया जा चुका है और अगले दो वर्षों में सभी उपभोक्ताओं को प्रिपेड मीटर लगा दिया जाएगा ।

महोदया, एक समय था जब बिहार की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर पिछले पायदान पर की जाती थी, वहीं राज्य में एन.डी.ए. सरकार के बनते ही बिहार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में प्रतिदिन कामयाब हो रही है । ग्रामीण क्षेत्रों की सुदूर बसावटों को जोड़ने में बिहार ने देश के अन्य राज्य की तुलना में सबसे तेजी से निश्चित समय-सीमा में कार्य को पूरा किया है । वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना में तीन लाख तैतालीस हजार चार सौ अठारह बसावटों को जोड़कर बिहार ने पूरे देश में पहला स्थान प्राप्त किया है ।....क्रमशः

टर्न : 08/कृष्ण/15.02.2019

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : क्रमशः : महोदया, राज्य सरकार ने बसावटों के बाद उप टोलों तक संपर्कता पहुँचाने का निर्णय लिया है । इसके अतिरिक्त 557 किमी0 पी0एम0जी0एस0वाई0 के तहत सड़क बनाकर बिहार में, पूरे देश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है । ग्रामीण क्षेत्रों में 1 लाख 29 हजार किमी0 सड़क के विरुद्ध अबतक करीब 1215.99 किमी0 सड़कों का निर्माण किया जा चुका है और इतने बसावटों को सड़कों से जोड़ दिया गया है ।

महोदया, सरकार द्वारा राज्य को स्वच्छ रखने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं, जिसमें 7 निश्चय के तहत सबको स्वच्छ पानी एवं शौचालय उपलब्ध कराना प्रमुख है । इसके अतिरिक्त डोर टू डोर सूखा कचरा एवं गीला कचरा उठाव की शुरूआत कर दी गयी है तथा इसके निस्तारण हेतु वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का भी शिलान्यास किया गया है ।

महोदया, पर्यावरण को दूषित होने से बचाव हेतु पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में 25 अक्टूबर, 2018 से तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 25 नवंबर, 2018 से पॉलिथिन को प्रतिबंधित किया गया है ।

महोदया, राज्य सरकार शौचालय निर्माण की दिशा में काफी तेजी से कार्य कर रही है। वर्ष 2014 में जहां 22 प्रतिशत घरों में शौचालय था वहीं वर्ष 2017-18 में 8.73 लाख एवं 2918-19 में 58.22 लाख सहित कुल 1.7 करोड़ व्यक्तिगत शौचालय का स्वनिर्माण लाभुकों द्वारा कराया गया है। वर्तमान में राज्य के 147 प्रखंड 363 ग्राम पंचायत एवं 18.723 ग्रामों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया जा चुका है।

महोदया, जीविका के तहत अबतक गठित 82 लाख स्वयं सहायता समूहों से 96.50 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है तथा 52 हजार ग्राम संगठन और 878 संकुल स्तरीय संघों का गठन किया है।

महोदया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अबतक स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 12.76 लाख सदस्यों का बीमा कराया गया है।

महोदया, समेकित मुर्गी विकास तथा एकीकृत बकरी भेड़ विकास योजना के तहत 2.5 लाख परिवारों को मुर्गी एवं बकरी पालन से जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त 8 लाख छोटे और सीमांत कृषकों को योजना से जोड़ा गया है।

महोदया, कौशल विकास एवं नियोजन के तहत 2018 में अबतक कुल 2.30 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें स्वनियोजित किया गया है। महोदया, आज राज्य में सुशासन की सरकार है। अपराध पर रोक-थाम करने हेतु सरकार संकल्प है और उसी दिशा में अपना कार्य कर रही है। आज अपराधी लगातार पकड़े जा रहे हैं और उन्हें सजा भी मिल रही है।

सभापति (श्रीमती रंजु गीता) : अब आप समाप्त कीजिये।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : महोदया, एक मिनट में समाप्त करता हूं। महोदया, एन0 डी0 ए0 गठबंधन की सरकार शाराबबंदी और भ्रष्टाचार के मुद्द पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। आज सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचारी लोग प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं। यह सरकार की भ्रष्टाचार की रोक-थाम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज बड़े-बड़े पदाधिकारी एवं कर्मचारी रिश्वत लेते हुये पकड़े जा रहे हैं।

महोदया, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इस सदन में माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को गरीब जनता की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह पिछले दिनों उन्होंने 60 वर्ष की आयु के ऊपर के जो गरीब लोग थे जिनको बी0पी0एल0 से छांटा गया था, अब उनको भी पेंशन मिलेगा और पत्रकार भाईयों को भी पेंशन मिलेगा। इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और और माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं, श्री श्रवण कुमार, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास सदन में बैठे हुये हैं, अपने क्षेत्र कुढ़हनी विधान सभा जो 39 पंचायत का एक बड़ा प्रखंड हैं। इसलिए उससे 14 पंचायतों को अलग करके मनियारी को एक अलग प्रखंड बनाया जाय, जिससे सरकार की जनकल्याणकारी योजनाएं जन-जन तक

पहुंच सके। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बोलने का समय दिया। सब लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं।

सभापति (श्रीमती रंजु गीता) माननीय सदस्य श्री उमेश सिंह कुशवाहा ।

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : सभापति महोदया, सरकार द्वारा पेश किये गये लेखानुदान के पक्ष में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जो ए०पी०एल० और बी०पी०एल० का झमेला था, उसको खत्म कर 60 वर्षों के ऊपर के आयुवालों को वृद्धावस्था पेंशन लागू किया है, इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार प्रकट करता हूं।

महोदया, कुछ वर्षों में बिहार विकसित राज्य बननेवाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास की ओर अग्रसर है। न्याय के साथ विकास, 7 निश्चय कार्यक्रम जो बिहार के विकास में चार चांद लगा रहे हैं, जिससे बिहार के सभी पंचायतों, सभी वार्डों में जिसकी तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहा है। इस उपलब्धि से बिहार की प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई है। हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि सात निश्चय योजना से हो रहा है बिहार का कल्याण, नीतीश कुमार जी को याद करेगा सारा हिन्दुस्तान।

महोदया, मैं सरकार की कुछ उपलब्धियों की चर्चा करना चाहता हूं। कृषि रोड मैप, मानव विकास मिशन, कौशल विकास मिशन, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, मूलभूत सुविधायें, हर घर शौचालय निर्माण, हर घर नल का जल, हर घर बिजली की उपलब्धता, हर घर तक गली, नाली निर्माण ये उपलब्धियां आकाश में सीढ़ी के निर्माण जैसे बढ़ रही हैं।

महोदया, आज जो बिहार में जो चौमुखी विकास हो रहा है, जिसका प्रतिफल है कि बिहार में विकास की गति और विकास का दर 11.3 प्रतिशत है, जो सर्वाधिक सभी राज्यों से ऊपर है, यह बिहार सरकार नहीं कह रही है, यह केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन का हाल का रिपोर्ट है।

महोदय, किसी भी क्षेत्र को लीजिये, शिक्षा के क्षेत्र को लीजिये, आज बिहार के विद्यार्थी, बच्चे देश में ही नहीं, विदेशों में भी अपना नाम रौशन कर रहे हैं।

कमशः

टर्न-9/अंजनी/दि0 15.02.2019

श्री उमेश सिंह कुशवाहा : क्रमशः.... शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी कई योजना कार्यक्रम चला रहे हैं। किसान शिक्षा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, युवा कुशल कार्यक्रम, बी0पी0एस0सी0 की मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 50 हजार रूपये का प्रोत्साहन, यू0पी0एस0सी0 की तैयारी के लिए एक लाख का प्रोत्साहन सरकार के द्वारा जो घोषणा की गयी थी, वह

दिया जा रहा है। महोदया, कृषि के क्षेत्र में भी अद्भूत कार्य हुआ है कृषि रोड मैप बनाकर। मैं वैशाली जिला से आता हूँ और वैशाली को तो आप जानते ही हैं कि वैशाली सब्जी उत्पादन में अग्रणीय है। सब्जी के क्षेत्र में, जो हमारे किसान उत्पादन करते हैं, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब्जी फेडरेशन बनाने का काम किया है। अभी पॉयलेट प्रोजेक्ट के तहत पांच जिला बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, पटना एवं नालन्दा को टेस्ट के रूप में किया जा रहा है। इन पांचों जिला में 97 प्रखंड हैं और 97 प्रखंडों में प्रखंड सब्जी उत्पादन सहकारिता समिति का गठन हो गया है। उसका निबंधन हो गया है। समिति का मुख्य काम है कि जो हमारे किसान सब्जी उत्पादन करते हैं, सब्जी उगाते हैं, उनके सब्जी का कलेक्सन कर जो उचित भाव है, वह भाव दिलाना है। जो यूनियन बना है, उसका काम है कि मार्केटिंग उपलब्ध कराने का। महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना था कि हर भारतवासी के थाली में एक बिहार का व्यंजन हो, वह सपना साकार होते दीख रहा है। महोदया, आज हर भारतवासी के थाली में बिहार का सब्जी होगा और देश के चारों दिशा में बिहार की सब्जी का आयात होगा। बिहार सब्जी के उत्पादन में बहुत आगे है और आगे बढ़ रहा है। आप किसी भी क्षेत्र को लीजिए, सभी जगह विकास हो रहा है। महोदया, विपक्ष के सदस्य तो हैं नहीं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि 15 सालों में, आप सभी जानते हैं, सदन के सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि 15 वर्षों में उनलोगों ने क्या किया, किस तरह बिहार में लोग जिन्दगी काटने पर मजबूर थे, वे किसी तरह जीने को मजबूर थे लेकिन आज जबसे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के हाथ में सत्ता का बागड़ेर दिया गया, तब से 13 वर्षों में बिहार ने जो उच्चाई प्राप्त किया है, वह देश ही नहीं, दुनिया में सबसे आगे है। जिसके कारण आज बिहार का नाम लिया जा रहा है, बिहार अपना नाम रोशन कर रहा है। महोदया, हर क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है। मैं जितना भी गिनाऊं, वह बहुत कम पड़ेगा और चर्चा करूँ तो वह भी कम पड़ेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आनेवाले समय में बिहार और विकसित करेगा। बिहार में चौमुखी विकास हो रहा है और ऐसा नेता के नेतृत्व में हमलोग काम कर रहे हैं, जिसके कारण आज अच्छा-से-अच्छा काम हो रहा है। विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष मुद्दाविहीन है, इसलिए हंगामा करना ही उनका लक्ष्य रहता है, वे चाहते हैं कि किसी-न-किसी तरह का बहाना बनाकर सदन का बहिष्कार करें। महोदया, आज सरकार द्वारा जो लेखानुदान पेश किया गया है, मैं उसका पुरजोर समर्थन करता हूँ। आपने जो मुझे बोलने का समय दिया उसके प्रति आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

सभापति(श्रीमती रंजु गीता) : माननीय सदस्य श्री अनिल सिंह जी।

श्री अनिल सिंह : सभापति महोदया, सरकार द्वारा लाये गये लेखानुदान प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। महोदया, मैं नये माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि लेखानुदान है क्या और क्यों लाया जाया है तथा बजट और लेखानुदान में क्या अन्तर है? महोदया, बजट पूरे वर्ष के लिए लाया जाता है जबकि विशेष परिस्थिति को ध्यान में रखकर जैसे अभी चुनाव सर पर है, वैसी परिस्थितियों में लेखानुदान का प्रस्ताव लाया जाता है। महोदया, मैंने यह बात इसलिए कही कि वित्तीय कुशल प्रबंधन से ही फरवरी-मार्च में पूर्ण बजट लाया जा सकता है अन्यथा लेखानुदान प्रस्ताव लाया जाता है और यदि आम तौर पर हर वर्ष लेखानुदान का प्रस्ताव लाया जाय तो उससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। महोदया, हमारे राज्य का वार्षिक बजट इस वर्ष 2 लाख करोड़ से अधिक हो गया है। यह तभी संभव है, जब माननीय मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आपसी समन्वय के साथ कुशल प्रबंधन करते हों। मुख्यमंत्री को प्रशासनिक दायित्व के साथ-साथ अन्य दायित्व का निर्वहन करना पड़ता है लेकिन यदि वित्तीय प्रबंधन नहीं हो तो यह व्यर्थ हो जायेगा महोदया। महोदया, मैं बताना चाहता हूँ कि बार-बार विपक्ष के द्वारा कई प्रकार की बातें सदन के अन्दर की जाती हैं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार हो पूर्णरूपेण अपराध पर और भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं कर सकती है लेकिन अगर इच्छाशक्ति मजबूत हो और चाहत अगर हो तो निश्चित रूप से उसपर विराम लगाया जा सकता है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार पर आज सरकार कर्तव्यनिष्ठ है और प्रयास कर रही है, जिसके कारण उसका प्रतिफल भी सामने आ रहा है। आज समावेशी विकास की बात सरकार करती है। आप देखेंगे कि एक तरफ जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने हेतु विधेयक लाया गया है और वहां दूसरी तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं कि किस प्रकार से पहल की जाय कि सभी विश्वविद्यालयों में विभागवार रोस्टर के बदले पूर्ववत् शिक्षकों की बहाली हो। यह समावेशी सोच का ही परिचायक है। महोदया, मैं भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा चलायी जा रही कुछ जनोपयोगी योजनाओं के बारे में जिक्र करना चाहता हूँ। किसी भी समाज में दो सबसे बड़ी समस्यायें होती हैं। पहला बेरोजगारी और दूसरा वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा। आदरणीय मोदी जी ने, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने, भारत सरकार ने इन दोनों विषयों पर फोकस किया और बेरोजगारी को दूर करने के लिए कदम उठाया, जिसके तहत प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण का शुभारंभ किया, जिसमें नौजवानों को बगैर किसी परिसम्पत्ति को बैंक में गिरवी रखे हुए लोन देने की व्यवस्था की गयी है और जिसके कारण आज रोजगार सृजित हुए हैं और इसका सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है। यह मुद्रा योजना देश के स्तर पर बहुत आगे है और बिहार में भी काफी प्रगति है।

लेकिन इसमें बैंकों के सहयोग में कुछ कमी है। मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि इसपर मोनेटरिंग करते हुए बैंक को भी इसमें थोड़ी और गति लाने के लिए कहा जाना चाहिए।

महोदया, जहां तक वृद्धावस्था में आर्थिक सहारा की बात है, आदरणीय मोदी जी ने अटल पेंशन योजना शुरू की, जिसमें बहुत ही न्यूनतम राशि 60 वर्षों तक जमा करने पर एक हजार से लेकर पांच हजार रुपये तक प्रति माह पेंशन देने की व्यवस्था की गयी है। इसी अत्यधिक सफलता से उत्साहित होकर भारत सरकार ने अटल पेंशन योजना की अधिकतम पेंशन राशि पांच हजार रुपया से बढ़ाकर दस हजार रुपया तक करने की सैद्धांतिक सहमति बना चुकी है। महोदया, अभी परसों इस सदन में हम सबों ने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान देते हुए सदन में घोषणा की है कि 60 वर्ष से अधिक के प्रत्येक व्यक्ति को वृद्धावस्था पेंशन दी जायेगी। इसकी प्रशंसा चारों ओर हो रही है। महोदया, सरकार ने अद्भुत निर्णय लिया है और राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों में जे0ई0ई0-मेन्स की मेरिट लिस्ट से दाखिला लेने का निर्णय लिया है। यह मेधा को सम्मान देने वाला कदम है। मैं सदन को याद दिला दूं कि मैंने भी इस प्रकार का मिलता-जुलता एक गैर सरकारी संकल्प सदन में प्रस्तुत किया था।

(क्रमशः)

टर्न-10/राजेश/15.02.2019

श्री अनिल सिंह, क्रमशः- जिसमें मैंने अनुरोध किया था कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में परीक्षा की मेधा सूची के Qualified but not selected विद्यार्थी को बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार पुलिस सेवा के लिए ले लिया जाय। मैं समझता हूँ वह दिन दूर नहीं जब सरकार इस दिशा में भी निर्णय ले लेगी।

महोदया, बिहार 2008-09 से ही लगातार रेवेन्यू सरप्लस वाला राज्य रहा है। इस राज्य में प्रति व्यक्ति आय 28,485 रुपये हो गयी है। महोदया निरंतर आगे बढ़ते रहने को ही प्रगति कहते हैं। जहाँ इस राज्य का बजट आकार 2005-06 में 26328 करोड़ रुपये था, जिसमें योजना मद में मात्र 6087 करोड़ था, वही 2019-20 का बजट दो लाख पाँच सौ एक करोड़ रुपये है, जिसमें योजना मद में एक लाख एक हजार तीन सौ इक्यानवे है। यह भी कुशल वित्तीय प्रबंधन का नमूना है कि योजना मद में जहाँ 2005-06 में बजट की एक चौथाई से भी कम राशि थी वही 2019-20 में योजना मद में आधी राशि है। यह इस प्रदेश को और बढ़ते हुए प्रदेश को इंगित करता है और बताता है कि हकारा प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर है। महोदया आज हमारे वित्तीय प्रबंधन के कारण ही आज सरकार जो काम कर रही है शिक्षा के क्षेत्र में ग्रामीण विकास के क्षेत्र में, ग्रामीण कार्य विभाग के क्षेत्र में, समाज कल्याण विभाग के क्षेत्र में,

पथ निर्माण विभाग के क्षेत्र में, स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में, उर्जा विभाग के क्षेत्र में, पी0एच0ई0डी0 विभाग के क्षेत्र में, पंचायती राज विभाग के क्षेत्र में, शहरी विकास व आवास एवं अन्य पर खर्च करेगी ताकि राज्य का विकास तेजी से हो सके । महोदय, राज्य सरकार 2019-20 में राज्य की 58 जेलों से पटना उच्च न्यायालय तथा राज्य के 62 न्यायालयों के बीच मल्टी विडियो कॉन्फ्रेसिंग सिस्टम से जोड़ने की दिशा में अग्रसर है । महोदया, मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना के तहत शुरू की गई हर घर नल जल योजना के लिए 4095 पंचायतों के 56079 वार्डों में पेयजल की सुविधा मुहैया कराने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है और ऐसे निरंतर कई कार्य सरकार द्वारा कराये जा रहे हैं । महोदया, राज्य सरकार शौचालय निर्माण की दिशा में काफी तेजी से कार्य कर रही है । वर्ष 2014 में जहाँ 22 प्रतिशत घरों में शौचालय था वहीं वर्ष 2017-18 में 8.73 लाख एवं वर्ष 2018-19 में अबतक 58.22 लाख सहित कुल 1.07 करोड़ व्यक्तिगत शौचालय का स्वनिर्माण लाभुकों द्वारा कराया जा चुका है । वर्तमान में राज्य के 147 प्रखंड, 363 ग्राम पंचायत एवं 18,723 ग्रामों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है । महोदया, जीविका परियोजना के तहत अबतक गठित 8.2 लाख स्वयं सहायता समूहों से 96.50 लाख से अधिक परिवारों को जोड़ा गया है तथा 52,000 ग्राम संगठन एवं 878 संकुल स्तरीय संघों का गठन किया गया है । महोदय, प्रधानमंत्री जीवनज्योति एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत अबतक स्वयं सहायता समूहों से जुड़े 12.76 लाख सदस्यों का बीमा कराया गया है । महोदया, समेकित मुर्गी विकास तथा एकीकृत बकरी एवं भेड़ विकास योजना के तहत 2.5 लाख परिवारों को मुर्गीया एवं बकरीपालन से जोड़ा गया है । इसके अतिरिक्त 8.1 लाख छोटे और सीमांत कृषकों को कृषि योजनाओं से जोड़ा गया है । महोदय, कौशल विकास एवं नियोजन के तहत वर्ष 2018 में अबतक कुल 2.30 लाख युवाओं को प्रशिक्षित कर उन्हें नियोजित / स्वनियोजित किया गया है । महोदय, आज राज्य में सुशासन की सरकार है । अपराध पर रोकथाम करने हेतु सरकार कृत संकलिप्त है और उसी दिशा में अपना कार्य कर रही है । आज अपराधी लगातार पकड़े जा रहे हैं और उन्हें सजा मिल रही है । महोदया, एनडीए गठबंधन की सरकार शराबबंदी और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जीरों टॉलरेन्स की नीति पर कार्य कर रही है । आज सुशासन की सरकार में भ्रष्टाचारी लोग दिन प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं । यह सरकार की भ्रष्टाचार के रोकथाम की प्रतिबद्धता को दर्शाता है । आज बड़े-बड़े सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी रिश्वत लेने के आरोप में पकड़े जा रहे हैं । महोदया, राज्य सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई कार्य कर रही है । वर्ष 2005 में जहाँ तक महीने में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर भाग 39 मरीज आते थे । वर्तमान में वही एनडीए सरकार द्वारा कई स्वास्थ्य योजनाओं के शुरू होने से आज दहसत से ज्यादा मरीज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाने लगे हैं और लोगों का भरोसा सरकारी

अस्पतालों पर बढ़ा है। महोदया, सरकार का यह लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सुविधा के लाभ राज्य के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। इसके लिए प्रखंड मुख्यालय के अतिरिक्त 3000 से 5000 की आबादी पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना की जा रही है। महोदया, परमाणु ऊर्जा आयोग, मुंबई एवं टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई के सहयोग से श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में एक विशिष्ट कैंसर अस्पताल की स्थापना की जा रही है। महोदया, केन्द्र की मोदी सरकार ने गरीबों के समुचित इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरूआत की है। यह विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसके अंतर्गत गरीब सरकारी और प्राईवेट अस्पतालों में सालाना पाँच लाख रूपये इलाज पर खर्च कर सकते हैं। इस योजना से बिहार के 1.08 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के 1,00,29,655 एवं शहरी क्षेत्र के 8,65,521 परिवार सम्मिलित हैं। महोदया, राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 550 सरकारी अस्पतालों एवं 60 प्राईवेट अस्पतालों को सूचीबद्ध किया है जिसमें 2.51 लाख लाभार्थियों को योजना का लाभ प्रदान करने हेतु गोल्डेन कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और 5,807 लाभुगों को लाभान्वित किया जा चुका है। महोदया, राज्य में अतिरिक्त 11 मेडिकल कॉलेज और एक डेंटल कॉलेज खोले जायेंगे। इसके अलावे 250 नया एम्बुलेंस की व्यवस्था, 150 वेलनेस सेंटर, 150 प्रकार के दवाओं की आपूर्ति एवं मरीजों को अस्पताल में कोई परेशानी नहीं हो के लिए टोल फी नम्बर 104 की सुविधा 24 घंटे प्रदान की गई है। महोदय, सरकार द्वारा पी0एम0सी0एच0, एन0एम0सी0एच0 एवं आई0जी0आई0एम0एस0 हेतु कार्य किए जा रहे हैं जिसके तहत पी0एम0सी0एच0को पाँच हजार बेड और एन0एम0सी0एच0 और आई0जी0आई0एम0एस0 को ढाई हजार बेड अस्पताल बनाने का कार्य चल रहा है। महोदया, राज्य सरकार गरीबों को उच्च एवं बेहतर तकनीकी शिक्षा सुलभ कराने की दिशा में भी कार्य कर रही है जिसके तहत प्रत्येक जिले में एक इंजीनियरिंग कॉलेज एवं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना की जा रही है ताकि बिहार के छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर ना जाए। अबतक 23 सरकारी और 7 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज बिहार में खोले जा चुके हैं। महोदया, पूर्व के समय में बिहार का नाम देश के बाहर अपराधिक गतिविधियों के लिए जाना जाता था और लोग यहां आने के नाम से डरते थे, वहीं जब से एन0डी0ए0 सरकारी बनी है राज्य विकास की दौड़ में काफी तेजी से अग्रसर है जिसके चलते राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक कायम करनी शुरू कर दी है। राज्य के खाते में राष्ट्रीय स्तर की दो और उपलब्धियाँ जुड़ गई जिसके तहत बिहार डीबीटी में देश में प्रथम स्थान और मातृवंदना में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। डीबीटी योजना के अंतर्गत वर्तमान में 62 लाख 57 हजार पेंशनरों को सीधे उनके खातों में पेंशन की धान राशि भेजी जा रही है जो पूरे देश में सर्वाधिक है। वहीं प्रधानमंत्री

मातृवंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को प्रथम जीवित संतान के लिए तीन किस्तों में सशर्त पाँच हजार रूपये डीबीटी के जरिए खाते में भेजे जाते हैं। अब तक 1 लाख 41 हजार 263 लाभार्थियों को लाभ की राशि का भुगतान किया जा चुका है। महोदय, वर्ष 2018-19 में 45.57 लाख किसानों का निबंधन किया जा चुका है तथा विभिन्न प्रकार के अनुदान की राशि आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजी जा रही है। महोदया, 2018-19 में अनुदान रहित मूल्य पर बिहार राज्य बीज निगम द्वारा 21 लाख किसानों को 96,000 किंवंटल गेहूं बीज का वितरण ऑन लाइन एप के माध्यम से किया गया है। महोदया, अनियमित मानसून तथा कम वर्षा होने के कारण राज्य के 24 जिलों के 280 प्रखंडों को सूखा ग्रस्त घोषित करते हुए वहां के किसानों को सिंचित क्षेत्र के लिए 13,000 रूपये प्रति हेक्टेयर तथा असिंचित क्षेत्र के लिए 6800 रूपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान की राशि का ऑन लाइन भुगतान किया गया। महोदया, विशेष उद्यान फसल विकास योजना के तहत जिलों की विशिष्टता के अनुसार उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण पैकेजिंग तथा ब्रॉडिंग के लिए 90 प्रतिशत तक अनुदान का प्रावधान किया गया है। महोदया, वर्ष 2018-19 में मिट्टी नमूना संग्रह का लक्ष्य 6.54 लाख के विरुद्ध अभी तक 5.63 लाख का संग्रह कर 3.60 लाख नमूनों का जांच किया गया है। महोदया, सरकार द्वारा सिंचाई के लिए 350 रु0 प्रति एकड़ प्रति सिंचाई डीजल अनुदान का बढ़ाकर 500 रु0 प्रति एकड़ प्रति सिंचाई कर दी गई है। इस वर्ष धान फसल के लिए 3 सिंचाई के बदले 5 सिंचाई तथा रब्बी मौसम में गेहूं के लिए 3 के स्थान पर 4 एवं मक्का के लिए 2 के स्थान पर 3 सिंचाई के लिए डीजल अनुदान की स्वीकृति प्रदान की गई है।

क्रमशः..

टर्न-11/सत्येन्द्र/

श्री अनिल सिंह(क्रमशः) महोदया, राज्य की एन0डी0ए0 सरकार ने किसानों के हित के लिए बिहार राज्य फसल सहायता योजना लागू किया है। ऐसी योजना शुरू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। इसके अन्तर्गत एक हे0 में एक फीसदी से ज्यादा फसल की क्षति होने पर 7,500 रु0 एवं 20 फीसदी से अधिक नुकसान होने पर 10 हजार रु0 मिलेंगे। उसी प्रकार 2 हे0 में 1 फीसदी से ज्यादा फसल क्षति पर 15,000 रु0 तथा 20 प्रतिशत से अधिक नुकसान होने पर किसानों को 20 हजार रु0 दिये जायेंगे। इस योजना से एक करोड़ से ज्यादा किसानों को इकट्ठा लाभ मिलेगा। महोदया, राज्य की तरक्की एवं खुशहाली कृषि एवं पशुपालन पर निर्भर है। पशुपालन एवं कृषि विभाग में विकास हेतु राज्य की एन0डी0ए0 सरकार निरंतर कार्य कर रही है जिससे बिहार राष्ट्रीय स्तर पर पशुपालन एवं कृषि क्षेत्र में आवार्ड जीतकर बिहार का नाम रौशन किया है। सरकार

पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन एवं अंडा उत्पादन के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य कर रही है ताकि राज्य अंडा एवं मत्स्य पालन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो सके। वर्ष 2017 में पशुओं के टीकाकरण की उपलब्धि पर राष्ट्रीय स्तर पर “ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड” मिलने से राज्य गौरवान्वित हुआ है। महोदया, राज्य सरकार द्वारा पशु चिकित्सकों को मानव चिकित्सकों की तरह वेतन सहित सभी सुविधाएं देने की घोषणा से चिकित्सकों का मनोबल ऊँचा हुआ है और महोदया, राज्य सरकार संविदा पर नियुक्त पशु चिकित्सकों के मानदेय में दोगुने से अधिक वृद्धि करते हुए इसे 29,500/- रु0 से बढ़ाकर एम0बी0बी0एस0 के समतुल्य 65,000/-रु0 कर दिया गया है, साथ ही साथ सरकार द्वारा 581 नवचयनित पशु चिकित्सकों की नियमित नियुक्ति की जा रही है। महोदया, सड़क निर्माण के क्षेत्र में राज्य सरकार तीव्र गति से कार्य कर रही है। आज सरकार द्वारा कई फ्लाईओवर सहित अनेक सड़कों का निर्माण कार्य किया जा रहा है ताकि राज्य के किसी भी जगह से राज्य के मुख्यालय आने में उन्हें पांच घंटे से ज्यादा का समय न लगे, उसके भीतर राज्य मुख्यालय तक आ सकें अपने चिकित्सा के लिए या समुचित अपने किसी कार्यों के लिए। महोदया, राज्य सरकार ने जिला और प्रखंड स्तर पर धान, गेहूं, आलू, मत्स्य, गौ पालन से अधिक उत्पादन पाने वाले किसानों को पुरस्कृत करने का काम कर रही है ताकि इनके मनोबल को बढ़ाया जा सके और राज्य दुग्ध मत्स्य पालन एवं अनाज के क्षेत्र में अधिक उत्पादन कर सकें। इसके लिए किसान सम्मान योजना लागू किया गया है जिसके तहत प्रखंड स्तर पर 2670 किसानों को, जिला स्तर पर 190 किसानों को और राज्य स्तर पर कुल पांच किसानों को सम्मिलित किया जायेगा। महोदया, राज्य में देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है जिसका मुख्य कारण है लॉ एंड आर्डर, आज यहां पर कानून का राज स्थापित हुआ है जिसके कारण पर्यटक बिहार की ओर आकर्षित हुए हैं। महोदया, इसका मुख्य कारण पर्यटकीय सुविधाओं का विकास होना है। राज्य में 600 करोड़ के प्रधानमंत्री पैकेज से पर्यटकीय सुविधाओं का विकास हो रहा है जिसके अन्तर्गत कॉवरियां पथ, सुल्तानगंज से अजगैबीनाथ मंदिर का विकास, मोकामा(मुंगेर) में रेन शोल्टर, बांका के जलेबिया, सुईया में मार्गीय सुविधाओं का विकास, तानकेश्वर में कैफटेरिया का निर्माण, कॉवर स्टैंड और सोलर लाईट लगाने का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री पैकेज के तहत जैन, महात्मा गांधी, बौद्ध, रामायण सर्किट का निर्माण एवं राजगीर, मंदार पर्वत, ब्रह्मयोनि, प्रेतशीला डोगेश्वरी पर्वत, वाणवार मुंडेश्वरी एवं रोहतास गढ़ में रोप-वे का निर्माण कराया जा रहा है। महोदया, सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और आज जो महोदया आज हमारे बगल में राजगीर में तालकटोरा झील में भगवान बुद्ध का विशाल प्रतिमा स्थापित कर पर्यटकों

को आकर्षित किया जा रहा है। महोदया, आपने मुझे बोलने का समय दिया आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री ललन पासवानः माननीय सभापति महोदया, सरकार के लेखानुदान के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूँ। कल भारत में हुए भारतीय सेना के जवानों पर घातक हमले में शहीद नौजवानों को मैं आपके द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, सदन भी श्रद्धांजलि दिया है और मैं भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से आपके माध्यम से मांग भी करता हूँ कि ऐसी ताकत जो हमारे जवानों पर हमला किया है, तत्काल मुहंतोड़ पाकिस्तान को जवाब देना चाहिए भारतीय सेना के सम्मान में। महोदया, निश्चित तौर से बिहार की बात करें तो देश में नरेन्द्र मोदी और सुशील मोदी, विकास की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर बिहार आज से लगातार 50-60 सालों से जो बिहार की हालत थी सड़कों के सवाल पर, बिजली के सवाल पर, पानी के सवाल पर, चाहे वह अपराध के सवाल पर लगता था कि डरावना बिहार है, अपहरणों का बिहार था, हत्या और बलात्कार का बिहार था, कभी शंकर बिगहा, बाथे, नारायणपुर, सेनारी, मियांपुर न जाने कितनी हत्याओं का दौर बिहार ने देखा है और वह बिहार को जब अतीत को याद करने के बाद लगता है कि आज बिहार कहां खड़ा है, उस समय बिहार कहां खड़ा था उसका मूल्यांकन करने से लगता है आसमान जमीन का अंतर है। हमलोग भी सासाराम जाया करते थे, 8 बजे के बाद गाड़ियां नहीं निकल पाती थी कि कब कहां उग्रवादियों का हमला होगा, कहां अपराधी लूट लेंगे, महिला पुरुष सब असुरक्षित थे इसलिए नीतीश कुमार जी और मोदी जी को जितनी बधाई दी जाय वह कम है कि बिहार में विकास की एक लंबी लकीर खींची गयी जो आने वाले दिनों में देश और राज्य याद करेगा कि कोई बिहार का मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री था जिसने बिहार की एक लंबी लकीर विकास की खींची है। हमने कहा कि कई चर्चाएं सामाजिक परिवर्तन के राम मोहन राय सती प्रथा के खिलाफ ज्योति राव फूले की पत्नी सावित्री देवी चाहे बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी संज्ञेय अपराध कहिये, चाहे उत्पीड़न कहिये इतनी बड़ी बिहार में और खासकर उत्तर भारत में जो ये लगातार हमले हो रहे थे, शराबबंदी की चर्चा हम बाद में करें लेकिन सामाजिक जो बुराईयां थीं, कुरीतियां थीं बाल विवाह, 10 साल, 12 साल, 6 साल की बच्चियों का शादी हो जाया करता था इस तरह से ज्योति राव फूले की पत्नी सावित्री देवी फूले ने पहली बार महाराष्ट्र में शुरू किया और उसके बाद देश के 28 राज्यों में नीतीश कुमार पहला मुख्यमंत्री जिन्होंने दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ एक सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई का शंखनाद ही नहीं किया बल्कि प्रतिबंध लगाया इसलिए मैं कहा कि कई सवालों पर नीतीश कुमार को बधाई दिया जा सकता है, देना चाहिए भी देश की राज्य की जनता को तब महोदय, चाहे वह सात निश्चय हो, चाहे महादलित समाज के सवेक टोला हो, बेरोजगार नौजवान जो हथियार उठाते थे कलम के

जगह पर उन्हें अवसर मिला । अभी सरकार कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं, अनुजाति उद्यमी रोजगार योजना, नीतीश कुमार जी ने शाराबबंदी किया, हमलोग इसी सदन में संकल्प लिये थे महोदया तो इसलिए हमने कहा है कि जैसे देश में नरेन्द्र मोदी पूरी दुनिया में आजादी के 70 वर्षों में पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री दुनिया में भारत के तिरंगा को सम्मानित करने का काम किया और गौरव प्राप्त किया, उसी प्रकार बिहार के 28 राज्यों में नीतीश कुमार ने बिहार में एक लकीर खींचा विकास का, सामाजिक समरसता का, गैरबराबरी का उसका कोई जोड़ नहीं है इसलिए मैं सुशील मोदी और नीतीश कुमार जी को बधाई देते हुए हमारे यहां महोदया, 6 अप्रैल को माननीय नीतीश कुमार जी पहाड़ पर गये थे । आजादी के 70 वर्षों में 40 साल, 50 साल कांग्रेस सत्ता में रही, माननीय सदस्य तो चले गये हैं, 15 साल लालू प्रसाद यादव की भी सरकार रही है (क्रमशः)

टर्न-12/मधुप/15.02.2019

...क्रमशः...

श्री ललन पासवान : करीब-करीब एक लाख की आबादी चुआरी का पानी पीती थी, बिजली का बल्ब ही नहीं देखा था । आदि मानव पहले रहा करता था, उसके शिला पट्ट हैं, शैल चित्र हैं । वहाँ डी०एफ०ओ० संजय सिंह की हत्या हुई थी, उग्रवादियों के अधिपत्य से पूरा कैमूरांचल लथपथ था । उसके पहले कई सामाजिक लड़ाईयां भी हुईं । कभी इटावा की तरफ से फूलन देवी का भी प्रादुर्भाव हुआ, सामाजिक तरीके से बहुत लड़ाईयां हुईं, जातीय संघर्ष हुए, कई लोग मारे गए । लेकिन पहली बार नीतीश कुमार के आने के बाद पूरा कैमूरांचल खाली हुआ । 30-35 साल की उम्र में जब हमलोग होश सम्भाले थे, पैचवाँ-छठवाँ में गए थे, उसके बाद पहली बार हमलोग एम०एल०ए० की हैसियत से जाकर वहाँ आठ दिन रहकर कैमूर की पहाड़ियों पर घूमने का काम किया, नीतीश कुमार जी भी गए । 130 करोड़ का सोलर का उन्होंने आदेश दिया, बिजली विभाग को, प्रत्यय अमृत जी को, बिजली विभाग के मंत्री आदरणीय विजेन्द्र यादव जी को, नीतीश कुमार जी को, सुशील कुमार मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि पहली बार सोलर लगाने का आदेश हुआ । एल एण्ड टी कम्पनी लगा रही है लेकिन हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, माननीय बिजली मंत्री जी अभी नहीं हैं, सरकार बैठी हुई है कि अभी तक डेढ़ साल हो गया लेकिन जिस तरह से तेजी से काम होना चाहिए, थोड़ा और रफ्तार होना चाहिए, 600-700 गॉव गरीबों का, आदिवासियों का, वनवासियों का बाकी है । माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे, कहे थे कि विद्युतीकरण होगा, वन विभाग के पास उसका है एन०ओ०सी० अनापत्ति प्रमाण पत्र कैमूर और रोहतास का, दोनों जिला का बाकी है, डिप्टी सी०एम० माननीय सुशील जी होंग तो सुन रहे होंगे, सरकार सुन रही

होगी, जल्दी हो जाता और जो सोलर नहीं लगा है बचा गाँव, लोगों की अपेक्षाएँ थीं, नीतीश कुमार जी को, सुशील मोदी जी को, बिजली विभाग को, विजेन्द्र यादव जी को, कमीशनर प्रत्यय अमृत जी को याद करेगा, एक तरफ जिस तरह से भगवान को याद करता है जीवन भर, रात में लोगों का गाँव पता नहीं चलता था कि किस गाँव में कहाँ जायेंगे, रास्ता भूल जाता था, वनवासी, आदिवासी ढूँढते रहता था इसलिए सोलर और जल्दी लगे और परमानेंट बिजली का माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया था, एनोओ०सी० हो जाय और जल्दी वहाँ विद्युतीकरण हो जाय उन गरीबों का। माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देते हैं कि 44 गाँव पर सोलर ड्यूयेल पम्प पीने का पानी, पशुओं के पानी के लिए भी टेंडर हुआ है, यथाशीघ्र काम हो जाय फिर चुनाव भी है।

महोदया, झारखण्ड और बिहार को जोड़ने वाली सबसे बड़ी योजना है पंडुका पुल, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के पैकेज में शामिल था, डी०पी०आर० बनकर चला गया है स्वीकृति के लिए भारत सरकार में माननीय नितीन गडकरी जी के यहाँ है, माननीय नन्द किशोर जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सुशील मोदी जी से आग्रह करेंगे कि चुनाव से पहले उसकी स्वीकृति हो जाय, निविदा निकल जाय, भले अब शिलान्यास नहीं हो पायेगा, होगा कि नहीं होगा लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि विशेष परिस्थितियों में भी उस पंडुका पुल की स्वीकृति हो जाय। मुम्बई की दूरी लगभग 400-500 किमी० की कम हा जायेगी। क्योंकि हम उधर से जाते हैं 2100 किमी०, इधर से हम चोपन होकर जायेंगे अगर पंडुका पुल बनता है तो पाँच राज्यों को जोड़ने वाली सड़क 106 में जाकर रेणुकोट से मिलती है, 106 में खेलगाँव, अम्बिकापुर, नागपुर, रायपुर होते हुए 500-600 किमी० की दूरी कम होगी और पटना से भी मुम्बई का रास्ता स्कॉर्पियो और अन्य गाड़ियों से शुरू कर सकते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है और प्रधानमंत्री जी के 2 हजार करोड़ के पैकेज में अलग से शामिल था।

महोदया, एक बात और आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहते हैं कि जितने बाकी गाँव हैं सोलर वहाँ जल्दी लगे और विद्युतीकरण उन गरीबों के लिए परमानेंट हो जाय। काली चमड़ी वाले जो लोग हैं, जिन गरीबों का, दलितों का, शोषितों का, आदिवासियों का कोई दर्द नहीं सुना, नीतीश कुमार ने सुना इसलिए कोटिशः जबतक आदिवासी और पहाड़ रहेगा तबतक नीतीश कुमार का वह इलाका हमेशा आजीवन आभारी रहेगा और पूरा अधवारा, नौहट्टा, रोहतास, सासाराम, चेनारी का बड़ा हिस्सा पहाड़ों पर बसा हुआ है, लाखों नहीं हमको लगता है, जोड़िए तो लगता है कि 50 लाख के उपर करोड़ों के पशु चारा के अभाव में पहाड़ों पर रहते हैं, गर्मी जैसे तपती है, नदियों की पानी सुखती है तो सब नीचे पलायन कर आते हैं नहरों के किनारे अपने पशुओं की जान बचाने के लिए। कभी-कभी अभाव में पशु मर जाया करते थे

हजारों की संख्या में। इसलिए मैं नीतीश कुमार जी को जितनी बधाई दूँ, सुशील मोदी जी को, इस सरकार को, वह कम है।

महोदया, हमारे चेनारी और कैमूर को जोड़ने वाली एक पुल है कुद्रा नदी जो दुर्गावती को पार करती है, सवार के पास एक पुल है, माननीय विधायिका रिंकी पाण्डेय जी ने भी गैर-सरकारी संकल्प में इस विषय को उठाया था, बहुत महत्वपूर्ण पुल है, हम सरकार से आग्रह करेंगे कि उस पुल को किसी हालत में बना देने पर चेनारी और कैमूर की दूरी बड़ी आसान हो जाएगी। माननीय नन्द किशोर यादव जी, माननीय मंत्री, पथ निर्माण ने स्टेट हाईवे का सदन में ही घोषणा किया था - मॉ मुण्डेश्वरी से तारा चण्डी धाम और एक कर्मनासा से सड़क आती है पतेरी होकर आते हुए जुड़ती है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे करकट गढ़, जाने का रास्ता नहीं है मैडम, करकट गढ़ देश का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बन सकता है जिसकी अद्भुत सम्भावनाएँ हैं। वहाँ जगदहवा डैम उधर से आता है कर्मनासा से पतेरी नहर होते हुए चाँद और चाँद से जगदहवा डैम, जगदहवा डैम से अगर जिस तरह से स्टेट हाईवे मॉ मुण्डेश्वरी से तारा चण्डी धाम हुआ है, अगर पूरा जोड़ दिया जाय तो उत्तर प्रदेश के बाहर-बाहर लोग चले आयेंगे सीधे सासाराम से डेहरी होकर चले आयेंगे।

महोदया, निश्चित तौर से स्वास्थ्य सेवा में भी बड़ी प्रगति हुई है। पी0एम0सी0एच0, एन0एम0सी0एच0 और आई0जी0आई0एम0एस0 में सीट बढ़े हैं, 11 मेडिकल कॉलेज सरकार ने खोला है, खोल भी रही है, जी0एन0एम0, ए0एन0एम0 कई जगह। हम आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि कैमूर और रोहतास में, माननीय गोपाल नारायण सिंह जी को हमलोग बधाई दें, प्राइवेट कॉलेज एक खोले हैं लेकिन कैमूर और रोहतास के लोग 125 कि0मी0 चलकर हम हों चाहे पत्रकार हों, चाहे कोई साथी हो आम पब्लिक, अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ, अगर किसी को गोली लगी तो सीधे बी0एच0यू0 के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, पटना आने में 3.5 घंटा लगता है, तबतक उसकी मृत्यु हो जायेगी इसलिए कैमूर और रोहतास में एक मेडिकल कॉलेज की माँग हम सरकार से करते हैं कि विशेष परिस्थितियों में एक मेडिकल कॉलेज और ट्रॉमा सेन्टर जरूर होना चाहिए। कैमूर और रोहतास में माननीय नीतीश कुमार जी ने इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास किया है लेकिन मेडिकल कॉलेज जरूरी है, महोदया।

एक और आग्रह के साथ माननीय सभापति महोदया, हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि गुरुबत नदी पर उत्तर प्रदेश जाने वाले रास्ते में अधवारा से राबर्ट्सगंज जाने वाला 9-12 कि0मी0 सड़क खराब है, वह बना हुआ था, उखड़ गया है, सरकार से आग्रह करेंगे कि एक पुल बन जाय तो उत्तर प्रदेश और बिहार का आवागमन पहाड़ों से हमेशा होते रहा है, इसलिए हम इसके लिए आग्रह करते हैं।

गुप्ताधाम में माननीय श्रवण कुमार, मंत्री जी गए थे, इन्होंने वादा भी किया

था, एक पुल बनाया भी है माननीय संसदीय कार्य मंत्री और माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने, गुप्ताधाम जाने में हमेशा 50-30-25 लोग बह जाया करते हैं दर्शन करने के लिए, शिव की नगरी है, जहाँ भगवान शिव को भस्मासुर चहेट कर ले गया था, जहाँ भस्मासुर को अमरत्व का वरदान मिला हुआ था, वहाँ भस्मासुर भस्म हुआ था भगवान विष्णु की कृपा से । महोदया, वहाँ भी एक पुल बन जाय तो लोगों का बह कर मरने का काम बंद हो जाय ।

आग्रह एक और है, सन् 1974 में, हालाँकि 1974 से पैदा हुए नेतृत्व में ही भारत, दिल्ली और बिहार, लगभग सरकार इन्हीं लोगों के नेतृत्व में चल रही है, हम 1974 वाले नहीं हैं, हमलोग तो 1980-1982 वाले हैं, महोदया, 1974 में जो मीसा में, जो आंदोलन में शामिल थे, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश सरकार 25-25 हजार रूपया पेंशन देती है । कई सेनानी हमसे मिले, इसमें बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री जी 1974 के हैं, माननीय सुशील मोदी जी 1974 के हैं, श्रवण कुमार जी हैं, वीरेन्द्र भाई हैं, सुबोध जी हैं, हम यह नहीं कहते हैं, उस समय आरोप्सोप्सो हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेसवाद के खिलाफ सम्पूर्ण नौजवान एक तरफ इंकलाब करने के लिए खड़े थे इंदिरा गांधी के लालफीताशाही के खिलाफ । देश में बड़ा आंदोलन आजादी के बाद पहली बार, लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में पूरा देश हुंकार भरा था, लोकबंधु राजनारायण ने इंदिरा गांधी को हाईकोर्ट के फैसले के बाद, बरेली में गाना भी हुआ था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में..

...क्रमशः....

टर्न-13/आजाद/15.02.2019

..... क्रमशः

श्री ललन पासवान : भारत के प्रधान मंत्री को, दिशा बदल दिया था और उसको हराने का काम किया था । उस जयप्रकाश जी के नेतृत्व में लड़े हुए सेनानियों का सम्मान में बड़े फैसले सरकार को लेना चाहिए, जैस उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ ने दिया है 25हजार पेंशन, उनके परिवार को मेडिकल सुविधा, आने-जाने की सुविधा, उनके सेनानियों को पी0एफ0 और कई जगह कई सवाल हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जे0पी0 आन्दोलन से जुड़े, स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में गांधी जी के और सरदार पटेल जी के नेतृत्व में लोगों ने लड़ा, उसी तरह यह दूसरी लड़ाई आजादी की थी । आगे नहीं पता नहीं तीसरी लड़ाई होगी या नहीं होगी, लेकिन लगता है कि अधिकार के सवाल पर तीसरी भी लड़ाई हो सकती है । लेकिन जिन लोगों ने लड़ा, जिनके परिवार आज भी कहीं-कहीं हैं, ऐसे जे0पी0 सेनानियों को 25हजार के जगह पर हम तो कहेंगे कि 30हजार कर दीजिए, लेकिन निश्चित तौर पर जे0पी0 सेनानियों को जो मिसा पर थे और कई लोग 18 को, 19 को, 20 को, कभी औरंगाबाद, कभी सासाराम, बारी-बारी से

जिला के लोग बिहार विधान सभा के गेट पर, कई भाई पत्रकार थे और कई युवा वाहिनी के लोग थे, कई साथी हैं, जिन्होंने लड़ने का काम किया । वैसे जे०पी० सेनानियों को पूरी सुविधा जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को मिलता है, उसी तर्ज पर लोकनायक जयप्रकाश जी के नेतृत्व में लड़ने वाले लाल फिताशाही के खिलाफ में लड़ी गई दूसरी लड़ाई के सेनानियों को सारी सुविधा देने की मांग सरकार से करते हैं महोदया। तीसरी बात मैं सिर्फ आपसे कहना चाहूँगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आलोक में पता नहीं यह न्यायापालिका हम भी देश के वासी हैं, सम्पूर्ण भारत में 25 से 30 करोड़ आबादी अनुसूचित जातियों की होगी । लेकिन बार-बार न्यायापालिका दलितों के खिलाफ फैसला देती है । कभी इलाहाबाद देती है, कभी सर्वोच्च न्यायालय देती है । पता नहीं हमलोगों को इस देश का वासी नहीं मानती, हमको पता नहीं । माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े संवेदना के साथ कल के भाषण में उन्होंने कहा था कि 200 पर रोस्टर था और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद के फैसले को फैकल्टीवाईज कर दिया । हमारा 4 नम्बर रोस्टर है, 4 के बाद 10 नम्बर है और जब फैकल्टीवाईज होगा, तब हम कभी अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़ी जाति का न बेटा न बेटी कभी प्रोफेसर बन पायेंगे, न इंजीनियर बन पायेंगे, न मेडिकल में जा पायेंगे, हर जगह दिक्कतें हो जायेगी । इसलिए सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव लिया है और कहा है कि इसको जाना चाहिए ।

महोदया, हमारे यहां पथ निर्माण में माननीय नन्दकिशोर भईया जी के यहां, माननीय महेश्वर हजारी जी के यहां, माननीय शैलेश कुमार जी के यहां

सभापति(डॉ० रंजूगीता) : अब आप समाप्त करें ।

श्री ललन पासवान : बस एक मिनट, और वरीयता, दो साल की वरीयता में अनुसूचित जाति को प्रोमोशन नहीं मिला, दो साल के बाद मिला तो क्या बिजली विभाग, क्या पी०डब्लू०डी० विभाग, क्या भवन निर्माण विभाग, क्या ग्रामीण कार्य विभाग, सभी विभागों में महोदया एक नम्बर में कमलेश चौधरी हैं मुख्य अभियंता, लेकिन इनको डिमोशन कर दिया गया। महोदया, दूसरा इन्द्रजीत कुमार अनुसूचित जाति का है, ईश्वरी प्रसाद जी अनुसूचित जनजाति के हैं, सुरेश कुमार अनुसूचित जाति के हैं, ये फिडर वरीयता जो दिया गया, क्योंकि जो सामान्य जाति को पहले प्रोमोशन दिया गया, उसके बाद दो साल के बाद हमको प्रोमोशन मिला । हम मुख्य पदों से वर्चित हो गये, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करेंगे और हमने पत्र भी लिखा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको आप जॉच कराकर इसकी जो वरीयता है अनुसूचित जाति को और सब कोई मानता है कि माननीय नीतीश कुमार दलितों के पक्ष में, महादलितों के पक्ष में खड़े रहते हैं । इतने बड़े सरकार के प्रधान सचिव के द्वारा जो अनुमोदन हुआ है, पी०डब्लू०डी० के द्वारा अनुमोदन हुआ

है, सब में हमारे लोगों को डिमोशन कर दिया गया है। इसलिए इसकी जॉच कराकर उसकी वरीयता के आधार पर हमें प्रोमोशन में आरक्षण मिलनी चाहिए। जो मुख्य अभियंता थे, उनको नीचे कर देने पर आज कितना समाज डिमोलाईज होता है महोदया, इसलिए मैं आग्रह के साथ सरकार से कहना चाहता हूँ कि पदोन्नति में सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, उसके बाद सरकार जो पक्ष में है, सरकार उसकी वकालत करती है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव के बारे में कहा है कि 200 का जो रोस्टर है, वही चलना चाहिए। इसलिए सरकार सदन में जिस तरह से अन्य विभागों में हुआ है, हमारे लोग बहुत ही मर्माहत हैं। इसलिए इस सवाल को माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, माननीय विजेन्द्र यादव जी वरीय नेता बैठे हुए हैं, सभी लोगों को ध्यान में रखना चाहिए और उसकी नोटिफिकेशन की कॉपी है। इसलिए इसको लागू कराकर दलितों, शोषितों, गरीबों को, आदिवासियों को निश्चित रूप से इसका लाभ मिलना चाहिए सरकार के तरफ से ताकि हमलोग सदन के बाहर भी चिल्ला कर कह सकें कि नीतीश कुमार जी की सरकार, सुशील मोदी जी की सरकार, जैसे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर लोकसभा में नया बिल लाकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को अत्याचार अधिनियम पर मुहर लगाने का काम किया, उसी तरह यहां भी एक फैसला सरकार को लेनी चाहिए। इसलिए दोबारा माननीय नीतीश कुमार जी को, माननीय सुशील कुमार मोदी जी को और इस सदन को धन्यवाद देते हुए पुनः माननीय विजेन्द्र बाबू बिजली मंत्री जी से आग्रह करेंगे कि पहाड़ पर आपने भी कहा था कि पहाड़ पर ग्रीड जायेगा तो उस ग्रीड के प्रति आपका थोड़ी मदद हो जाय, कमीशनर से आदेश कराकर जो आपने वादा किया था कि गरीबों को, दलितों को, बनवासी को, आदिवासी को बिजली मिले और सोलर 700 गांव में अभी नहीं लगा है, डेढ़ से दो साल हो गया, इसको जल्दी लगवाकर इनको न्याय देने का काम करें।

बहुत, बहुत धन्यवाद।

श्री विद्यासागर निषाद : सभापति महोदया, मैं बिहार विनियोग विध्येक, 2019 के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। कुछ बोलने से पहले जम्मू काश्मीर में सी0आर0पी0एफ0 के जवान जो शहीद हुये हैं, उनके प्रति मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूँ और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ।

महोदया, जिस प्रकार से बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार दिन दुनी रात चौगुनी विकास कर रहा है। इसी का देन है कि 2005-06 के बजट की तुलना में 9 गुना ज्यादा 2 लाख 501 हजार करोड़ का बजट 2019-20 में आया है। निश्चित ही इस बजट से बिहार के और उज्ज्वल और अच्छे विकास होने की संभावना है। महोदया, खासकर के मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से बदलते हुए बिहार की ओर मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

महोदया, कल तक महिलाओं को पुरुष समाज से लड़ना पड़ता था, लेकिन हमलोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी की देन है कि महिलाओं को त्रिस्तरीय पंचायत में 50 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किये हैं और शिक्षक नियोजन में भी 50 प्रतिशत आरक्षण के साथ-साथ सरकारी नियोजन में भी 35 प्रतिशत आरक्षण देने का काम किये हैं, निश्चित ही आने वाले समय में यही काम बिहार के उज्जवल भविष्य को संवारने का काम करेगा। महोदया, आज बिहार का 65 प्रतिशत आबादी युवाओं की है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू ने अपने सात निश्चय में आर्थिक हल युवाओं के बल के माध्यम से सभी छात्र-छात्राओं को स्नातकोत्तर पढ़ाई एम0बी0बी0एस0, इंजीनियरिंग, बी0एड0, पॉलिटेक्निक एवं अन्य कोर्सों के लिए लड़कों को 4 प्रतिशत की दर से और लड़कियों को 1 प्रतिशत के दर से और दिव्यांगों को 1 प्रतिशत की दर से जो स्टुडेन्ट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन देने का काम कर रहे हैं, वह काफी सराहनीय है। इस योजना से निश्चित ही बिहार को उच्चतर शिक्षा में नया मुकाम दिलायेगा और नया बिहार और उन्नतशील बिहार बनाने में अहम रौल निभायेगा। महोदया, हर घर बिजली के क्षेत्र में कभी अंधकार में ढूबे रहने वाला बिहार फूटी हुई लालटेन में अंधकार में ढूबने वाला बिहार आज जगमगा रहा है। लोहिया स्वच्छ अभियान से सम्पूर्ण बिहार में शौचालय बनाये जा रहे हैं। इस योजना के पूर्ण हो जाने से बीमारी भी कम होगी और स्वच्छ और स्वस्थ बिहार बनेगा।

..... क्रमशः

टर्न-14/शंभु/15.02.19

श्री विद्या सागर निषाद : क्रमशः....महोदय, कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए अलग से बिजली के फीडर बनाये जा रहे हैं और किसानों को 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। हर खेत को पानी देने का काम हो रहा है। खेतों के मृदा शक्ति की जाँच हो रही है। छोटे एवं मध्यम किसानों को मधुमक्खी पालन एवं मशरूम उत्पादन में सहायता दिया जा रहा है एवं आपदा के समय किसानों को राहत भी दी जा रही है। महोदया, मत्स्यपालन के क्षेत्र में वर्ष 2005-06 में कुल 24 हैचरियां थी आज बिहार में कुल 151 हैचरी है जिसमें से करीब 125 क्रियाशील है। अब बिहार मत्स्य उत्पादन में भी आत्मनिर्भर हो रहा है। महोदया, किशनगंज में मत्स्यकी महाविद्यालय में पठन-पाठन इसी वर्ष से शुरू हुआ है। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि चूंकि मछली पालन हम निषादों का मूल पेशा रहा है एवं पारंपरिक रूप से मत्स्यपालन हम मल्लाहों का काम रहा है। अतः मत्स्यकी महाविद्यालय में निषाद समाज की छात्र-छात्राओं को नामांकन में 50 प्रतिशत आरक्षण देने की मांग करते हैं। दूसरी समस्या तालाब और भूस्तर नीचे जाने से तालाबों का जीर्णोद्धार भी बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए सभी तालाबों का जीर्णोद्धार करना भी बहुत जरूरी है। महोदया, अति पिछड़ों को पूर्व की सरकारें वोट बैंक और जिन्न समझा करती थी, लेकिन वर्ष 2005 के नवम्बर में

नीतीश बाबू के मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका ध्यान सदियों से दबे, कुचले, शोषित, पीड़ित, लांछित-वर्चित समाज पर गया और वर्ष 2005 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों को 20 परसेंट आरक्षण देकर समाज के मूलधारा में लाने का काम किया है। महोदया, यही नहीं इस समाज के विकास के लिए राजनीतिक, सामाजिक और अर्थिक क्षेत्र में भी बहुत बड़े काम हुए हैं यह काम नीतीश बाबू की देन है। पिछले वर्षों में जननायक कर्पूरी ठाकुर अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावास के छात्रों को 15 किलो अनाज और 1 हजार रूपया प्रति महीना छात्रवृत्ति देकर गरीब गुरुबों को पैसे की कमी के कारण पढ़ाई न छोड़े इसपर भी काम चल रहा है। महोदया, नीतीश बाबू ने बिहार में अति पिछड़े समाज को न्यायिक सेवा में भी आरक्षण दिया है जिससे अब गरीब गुरुबों के बच्चे भी जज बनकर निकल रहे हैं। अभी पिछले वर्ष बी०पी०एस०सी० के पी०टी० में और य०पी०एस०सी० के पी०टी० में पास करनेवाले अभ्यर्थियों को 50 हजार और य०पी०एस०सी० के अभ्यर्थियों को 1 लाख रूपये सहायता दी गयी है। इससे बिहार के बच्चे भी ज्यादा से ज्यादा य०पी०एस०सी० में उत्तीर्ण होंगे और आनेवाले समय में बिहार का परचम देश में लहरायेगा। इस पुनीत कार्य के लिए मैं अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को दिल की गहराइयों से साधुवाद, धन्यवाद देता हूँ। महोदया, शराबबन्दी, बाल विवाह और दहेज प्रथा के उन्मूलन पर बिहार सरकार काम कर रही है, आनेवाले समय में पूरे देश में यह नयी इबारत लिखेगा। शराबबन्दी का फायदा सबसे ज्यादा गरीब गुरुबे, शोषित, दलित, महादलितों को हुआ है और अब उनका जीवन दिन-प्रतिदिन खुशहाल हो रहा है। अब वे समझ रहे हैं कि उनके पैसे का प्रयोग शराब में नहीं करना चाहिए। अब वे अपने परिश्रम का कमाया धन बच्चों की शिक्षा, अपने रहन-सहन पर खर्च कर रहे हैं। इस काम के लिए भी मैं अपने नेता को धन्यवाद देता हूँ। महोदया, सबसे बड़ी बात है कि विपक्ष के साथी और कांग्रेस के साथी गांधी जी का सिर्फ पेटेन्ट कराने की बात करते हैं, लेकिन असल में उनके आदर्शों और मूल्यों की रक्षा करने का काम हमलोगों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ही करते हैं। गांधी जी का सपना चाहे ग्राम स्वराज्य हो जिसे हमलोगों के नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लागू किया तथा बापू के सम्मान में विशाल बापू सभागार बनाया तथा गांधी मैदान में बापू की 70 फीट की ऊँची प्रतिमा लगवाया तथा अब पूरी दुनिया में श्रेष्ठ बापू टावर बनवाया जायेगा। जो आनेवाली पीढ़ियों को बापू के विचारों से सारे संसार को अवगत करायेगा और गांधी जी के मूल्यों और आदर्शों का दर्शन करायेगा। मैं चाहता हूँ कि इस देश का हर युवा बापू के विचारों को अपने जीवन में उतारे तो निश्चित ही देश का कल्याण होगा। महोदया, इस देश में गांधी जी, लोहिया जी, जयप्रकाश जी तथा जननायक कर्पूरी ठाकुर जैसे महानायक अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देकर चले गये। चाहे गांधी जी के ग्राम स्वराज्य की बात हो, चाहे लोहिया जी के सप्तक्रांति की बात हो, चाहे जयप्रकाश जी के संपूर्ण क्रांति की बात हो, चाहे जननायक के अधूरे सपने को पूरा करने की बात हो इन सभी महापुरुषों को श्रद्धांजलि देना हमलोगों के नेता

आदरणीय नीतीश कुमार जी का काम है। जिसके तहत गरीब, गुरुबे, शोषित, पीड़ित, छात्रों, महिला और युवाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर काम किया जा रहा है। निश्चित ही बिहार सरकार के इस काम से उन महापुरुषों के आत्मशांति के साथ-साथ बिहार की 13 करोड़ जनता को सुख और आनंद की अनुभूति हो रही है। महोदया, राज्य के सभी वृद्धजनों के सम्मान में इसी सदन में हमलोगों के नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो 60 वर्ष के उपर सभी लोगों को पेंशन, पत्रकार, छायाकार को पेंशन देने का निर्णय लिया है। इसकी काफी सराहना हो रही है। इसके लिए अपने नेता आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। अभी लगभग डेढ़ वर्षों से एक बंगले पर विवाद चल रहा था उस मामले में मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि बशीर बदर साहब एक मशहूर शायर थे उनका एक सेर है -घरों पर नाम थे, नामों के ओहदे थे, बहुत तलाश किया, कोई आदमी न मिला। अंत में अपने नेता और आपके प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।

श्रीमती बेबी कुमारी : सभापति महोदया, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत लेखानुदान के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। महोदया, राज्य सरकार न्याय के साथ विकास के लिए कृत संकल्प है। सरकार राज्य की जनता को मूलभूत सुविधा पेयजल, शौचालय, बिजली तथा स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचना सड़क, गली, नाली, पुल आदि को विस्तार देने हेतु जोरशोर से प्रयासरत है। महिलाओं एवं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने एवं उच्च व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास करने का कार्य कर रही है। इन सब योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए धनराशि की आवश्यकता है। जिसका आकलन बजट में कर इस सदन से पारित करने का अनुरोध किया गया है। चूंकि चुनावी वर्ष है इसीलिए अभी लेखानुदान आया है ताकि आर्थिक संकट न हो और पूर्ण बजट पर जून-जुलाई के आसपास सरकार हम सभी सदस्यों से राय और सहमति लेगी। महोदया, एन0डी0ए0 की सरकार द्वारा जितने काम 2005 से अभी तक किये गये हैं उनकी जितनी सराहना की जाय वह कम है। कोई एक योजना ही नहीं है जो नाम लिया जा सके। ऐसी दर्जनों योजनाएं हैं जिनके बारे में देश-विदेश तक चर्चा हो रही है। महोदया, राज्य सरकार द्वारा शराबबन्दी के क्षेत्र में किये गये कार्यों का लोगों में शराब के खिलाफ आई जागरूकता के मद्देनजर राष्ट्रपति महोदय द्वारा बिहार को पुरस्कृत किया गया। महोदया, राज्य सरकार द्वारा अन्तर्जातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना के तहत आर्थिक दृष्टि से सरल बनाने के लिए 1 लाख रूपये अनुदान के रूप में प्रदान कर रही है ताकि समाज से जाति प्रथा एवं छुआछूत को समाप्त किया जा सके और दहेज प्रथा को हतोत्साहित किया जा सके। महोदया, राज्य में महिलाओं को सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राज्य की एन0डी0ए0 सरकार कई योजनाएं चला रही है। जिसमें बालिकाओं के संरक्षण, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वाबलंबन को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, कन्या भूषण हत्या एवं जन्म

निबंधन को प्रोत्साहित करने को 2 वर्ष की बालिकाओं का संपूर्ण टीकाकरण, लिंग अनुपात में बालिका शिशु दर को कम करने, बालिका शिक्षा को बढ़ाने, बाल विवाह पर अंकुश लगाने, कुल प्रजनन दर में कमी लाने और बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कन्या योजना चलायी जा रही है। महोदया, राज्य सरकार गरीबों को उच्च एवं बेहतर तकनीकी शिक्षा सुलभ कराने की दिशा में भी कार्य कर रही है, जिसके तहत प्रत्येक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलीटेक्नीक कॉलेज की स्थापना की जा रही है। महोदया, छात्र इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए राज्य से बाहर न जाय- अब तक राज्य में 23 सरकारी और 7 प्राइवेट कॉलेज खोले जा चुके हैं।

क्रमशः

टर्न-15/ज्योति/15-02-2019

क्रमशः

श्रीमती बेबी कुमारी : महोदय, आज बिजली की घर घर चर्चा हो रही है। बिजली सभी घरों में दे दी गयी है। फलस्वरूप प्रदूषण तो रुका ही है, लोगों की आंखों की रोशनी भी बची। इसीतरह से गरीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन दिया गया जिससे गरीब महिलाएं धुओं जनित बीमारियों से बचने के साथ साथ अपने आप को उत्साहित भी महसूस कर रही है। उनके मन में यह बात भी आयी है कि हम भी अन्य महिलाओं की तरह मुख्य धारा की एक सदस्य हैं। महोदया, आज जो हमारी एन.डी.ए. की सरकार जो काम कर रही है उससे आज गरीब महिलाओं में काफी उत्सुकता बढ़ रही है कि गरीब के हित के लिए केन्द्र और एनप0डी0ए0 की सरकार दोनों मिलकर विकास का जाल बिछा रही है। रोड की समस्या हो या बिजली की हो या शौचालय जितनी भी नयी योजना चल रही है, वह गरीबों के लिए जनहित की योजना चल रही है। इससे गरीबों में काफी उत्साह है। सदन के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि आज जो हमारी केन्द्र सरकार और राज्य सरकार जो भी योजना किसान- हमारे कृषि मंत्री बैठे हुए हैं और हमारे सभी माननीय मुख्य मंत्री से लेकर सभी मंत्री और सदस्यगण बैठे हुए हैं क्योंकि विरोधी तो नहीं है यहाँ, विरोधी का कुछ भी नहीं बचा है कि हम क्या करें। उनका कोई चारा नहीं है फिर पुनः हमारी एन.डी.ए. की सरकार जो योजना चला रही है, वह घर घर पहुंच रही है, विरोधी कह रहे हैं कि घर घर नहीं पहुंच रही है लेकिन कहीं सर्वेक्षण करा लें कि घर घर हमारी बिहार सरकार की एन.डी.ए. की योजना जो चल रही है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी के द्वारा जो चल रही है, घर घर में महिलाओं और गरीबों के बीच पहुंच रही है। महोदया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बोचहा की महान जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार और देश के जो जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति मैं श्रद्धा सुमन

अर्पित करती हूँ और यही सदन के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि उनके परिवार को भगवान जीने की शक्ति दे और यही मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूँगी कि जो जवान शहीद हुए हैं, उससे उनका परिवार ही नहीं बल्कि पूरा देश मर्माहत है। मैं उनके प्रति बहुत बहुत श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जयहिंद, जय भारत, जय बिहार।

सभापति(श्रीमती रंजु गीता): श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय जी ।

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय : महोदया, सदन में मुझे पहली बार बोलने का मौका मिला इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व और सभापति महोदया को धन्यवाद देना चाहूँगी। लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव के पक्ष मैं बोलने के लिए खड़ा हुई हूँ। महोदया, राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के चार महीनों के लिए यथा अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई अवधि के लिए लेखानुदान पारित करने का अनुरोध किया गया है। लेखानुदान पर निधियों की कुल आवश्यकता 77 लाख 33 हजार 852.96 लाख रुपये तक की है जिसमें राजस्व लेखे के अंतर्गत 62 लाख 5 हजार 869.45 लाख रुपये और पूंजीगत लेखे के अंतर्गत 15 लाख 27 हजार 983.51 लाख रुपये हैं। महोदया, मैं लेखानुदान संबंधी प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हुई हूँ। सरकार द्वारा इस राशि का खर्च सभी विभागों में विकास कार्य हेतु किया जायेगा। सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए कृतसंकल्पित है। विकसित बिहार के 7 निश्चय के तहत गांव और शहरों के सभी घरों को नल जल शौचालय, गली नली एवं बिजली की सुविधा चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करायी जा रही है। एक समय था जब महिलाएं शौच जाने के लिए अंधेरा का इंतजार करती थी। आज एक समय है जो माननीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा इस अंधेरा से आजादी मिली इसके लिए मैं बिहार की महिलाओं की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री एवं उप मुख्यमंत्री को लाख लाख बधाई देना चाहूँगी। महोदया, सरकार द्वारा पटना में आर0ब्लौक-दीघा 6 लेन सड़क, पूर्णिया, जमुई, समस्तीपुर में मेडिकल कॉलेज गया में मौड़ल कैरियर सेंटर बाल्मीकी टाईगर रिजर्व मुंगेर भीम बांध में इको टूरिज्म मुजफ्फरपुर में कैन्सर अस्पताल और हर प्रखण्ड में आर्थिक सहायता केन्द्र खोलने की दिशा में अग्रसर है। सरकार इस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक राशि शिक्षा, ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, समाज कल्याण, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, उर्जा, पी0एच0ई0डी0, पंचायती राज, शहरी विकास एवं आवास एवं अन्य पर खर्च करेगी ताकि राज्य का विकास तेजी से हो। इसमें संशय नहीं है महोदया, कि राज्य का विकास नहीं हो रहा है। राज्य का विकास आज दिन दुनी रात चौगुनी हो रहा है। हर क्षेत्र में विकास हो रहा है इसके लिए मैं अपनी सरकार को अपने बिहारवासियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगी। महोदया, राज्य सरकार 2019-20 में राज्य के 58 जेलों से पटना उच्च न्यायालय तथा

राज्य के 62 न्यायालयों के बीच मल्टी वीडियो कंफेन्सिंग सिस्टम से जोड़ने की दिशा में अग्रसर है। महोदय, मुख्यमंत्री 7 योजना के तहत शुरू की गयी हर घर नल योजना के लिए 4095 पंचायतों के 5669 वार्डों में पेय जल की सुविधा मुहैय्या कराने की दिशा में सरकार कार्य कर रही है। राज्य के सभी नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी पेय जल योजना के तहत शहरी क्षेत्र के हर घर को नल जल मुहैय्या कराने का लक्ष्य है। अबतक सभी नगर निकायों के 2379 वार्डों में काम शुरू हो चुका है जिसमें 329 वार्डों में काम पूरा किया जा चुका है तथा 2 लाख 76 हजार 8846 घरों को नल जल उपलब्ध कराया जा चुका है। राज्य के 21598 वार्ड बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आते हैं जहाँ पीने के पानी की समस्या है इनमें से 134 वार्ड में हर घर नल का जल योजना पूरी की जा चुकी है। इस वित्तीय वर्ष में 13 हजार 2871 फ्लोराईंड प्रभावित वार्डों को हर घर नल जल की योजना से जोड़ दिया जायेगा। सरकार प्रदेश के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज तथा पॉलिटेक्नीक संस्थानों में इन्टरनेट की सुविधा प्रदान करेगी साथ ही साथ सभी विश्वविद्यालयों के कॉलेज में वाई-फाई सुविधा प्रदान करने की दिशा में अग्रसर है। सरकार द्वारा 54 ए.एन.एम. और 23 जी.एन.एम. स्कूल खोले जायेंगे, इसके अतिरिक्त नालन्दा में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केन्द्र की शाखा स्थापित की जायेगी। सरकार तारेगना में एस्ट्रो ट्रॉज्म सर्किट का निर्माण करायेगी। सरकार द्वारा 2019-20 में व्यापक पैमाने पर नियुक्तियाँ होने जा रही है जिसमें स्वास्थ्य विभाग में 21571, पुलिस विभाग में साढ़े 13 हजार प्रयोगशाला प्रोधैगिकी के 1772 फार्मेसिस्ट के 345 चालक के 466 आशूलिपिक के 326, स्वच्छता निरीक्षके पद 276, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में लगभग 32 हजार पद, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में 581, पशु चिकित्सक 1392, असैनिक एवं अभियांत्रिक अभियन्ता के 558, दंत चिकित्सक के 295 जिसमें सहायक प्रोफेसर सम्मिलित हैं। महोदय, सरकार उर्जा के क्षेत्र में काफी तेजी से कार्य कर रही है। केन्द्र एवं राज्य की एन.डी.ए. सरकार प्रत्येक घर में बिजली पहुंचाने का कार्य तीव्र गति से कर रही है। महोदय, एक समय था।

सभापति(श्रीमती रंजु गीता): श्रीमती रंकी रानी पाण्डेय जी अब आपका समय समाप्त हो रहा है।
श्रीमती रंकी रानी पाण्डेय : महोदया, एक मिनट, मैं विपक्ष के लिए कहना चाहती हूँ कि ये लोग कहते हैं कि विकास नहीं हो रहा है। विकास क्यों नहीं हो रहा है आप विकास के चश्मे से देखियेगा तो विकास दिखेगा। अगर समंदर का पता लगाना है तो गहराईयों के दामन थाम कर देखो और विकास के रफ्तार को देखना है अपनी आंखों से तो चारा घोटाला एवं अलकतरा घोटाला के चश्में को उतार कर देखो।

क्रमशः

टर्न-16/15-02-2019/बिपिन

श्रीमती रिंकी रानी पाण्डेय : क्रमशः माननीय महोदया, मैं अपने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जी के लिए बिहार की बेटियों की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूं -

‘अगर खुदा नहीं होता तो यह तख्तो-ताज कौन देता,
अगर माननीय मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री नहीं होते
तो बेटियों को सम्मान का सरताज कौन देता ।’

बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय महोदया, मुझे समय देने के लिए ।

सभापति (श्रीमती रंजु गीता) : बहुत-बहुत धन्यवाद । बहुत-बहुत साधुवाद रिंकी जी ।
माननीय सदस्य श्री मनोज कुमार ।

श्री मनोज कुमार : आज मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और विशेषकर विपक्षी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उनके अनुपस्थिति ने आज हमलोगों को पुनः बोलने का मौका दिया।

महोदया, आज वित्तीय वर्ष 2019-20 के चार महीने के लिए लेखानुदान का जो बजट को पास करने का प्रस्ताव प्रभारी मंत्री के द्वारा पेश किया गया है और लगभग यह चौहत्तर हजार करोड़ रूपए का प्रस्ताव है और चूंकि हमलोगों ने दो लाख करोड़ से उपर का बजट इस वित्तीय वर्ष के पूरे बारह महीने के लिए पेश किया है और इस चार महीने में सरकार की अन्य आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए और कई योजनाएं हैं और खासकर जब माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक अप्रील, 2019 से वृद्धा पेंशन में और पत्रकारों के पेंशन की जो एक महान घोषणा इसी सदन के अंदर इसी सत्र में हुआ है, इसलिए आवश्यक है कि इस लेखानुदान बजट को सर्वसम्मति से पास किया जाता । आज क्या पक्ष, क्या विपक्ष, सारे लोग अगर हमलोग ध्वनिमत से प्रस्ताव पास करते तो एक यह अलग बात होती । खैर, विपक्ष में अब इतना साहस नहीं रह गया है कि बिहार के बढ़ते कदमों को और अर्थ व्यवस्था में जो उछाल आया है जिसकी रफ्तार से हम भारत की अर्थ व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण, एक मजबूत कदम के साथ चल रहे हैं । यह विपक्ष के सदस्यों को रास नहीं आ रहा है क्योंकि ये विपक्ष के लोग जिस दिन इस बिहार के विधान सभा में इसी सदन में जो बजट पेश करके गए थे, 2004-05 का बजट, जो लगभग चौबिस हजार करोड़ का बजट है और मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि जब पिछले वित्तीय वर्ष में हमलोगों ने एक लाख छिहत्तर हजार करोड़ के इस बजट को पेश किया था तो जो बजट वे पिछली बार छोड़कर गए थे उतने का बढ़ोत्तरी कर, हमलोगों ने जोड़कर इस विधान सभा में पेश किया है जो दो लाख पाँच हजार करोड़ रूपए का हुआ है । इन्हें यह पता नहीं चल रहा है कि बिहार का विकास दर 11 प्रतिशत से उपर कैसे चल रहा है । इन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि पिछले दशकों में लगातार हम दो

अंकों में विकास दर कैसे हासिल कर रहे हैं। इनकी बेचैनी स्वाभाविक है और विरोधियों को एक उपलब्धि सुनने का साहस इनके पास नहीं रह गया है। इसलिए स्वाभाविक है, इनकी मनोदशा को समझता हूँ और इसलिए आज इस महत्ती विषय में जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो आज ये मौजूद नहीं हैं।

खैर, मैं आना चाहूँगा कि बिहार की अर्थ व्यवस्था जब पिछले बार माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने एक लाख छिह्न्तर हजार करोड़ का बजट पेश किया था और हमलोग काफी गौरव से भरे हुए थे क्योंकि हम उस समय आसपास में, उप मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि गुजरात का भी जो बजट है इस वित्तीय वर्ष का वह लगभग एक लाख अस्सी हजार करोड़ रूपए का है, बंगाल का उस साल का बजट लगभग दो लाख करोड़ रूपए का था और आज हम इस सत्र के साथ में खड़े हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा नरेन्द्र मोदी जी की, अरूण जेटली जी की टीम को जिन्होंने जी.एस.टी. को लाने के बाद में जिस हिसाब से भारत की अर्थ व्यवस्था बढ़ रही है आज हम विश्व की छठी बड़ी अर्थ व्यवस्था बन चुके हैं और इस जी.एस.टी. एरा में मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चार-पांच वर्षों में जो सारे पूरे विश्व की वित्तीय संस्थाओं की, अर्थशास्त्रियों का जो अनुमान है, हमलोग आने वाले चार-पांच वर्षों में अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी अर्थ व्यवस्था बनेंगे। यह जी.एस.टी. एरा की उपलब्धि होगी और उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं यहां प्रस्तुत करना चाहूँगा कि पिछले वित्तीय वर्ष में जहां केंद्रीय करों में हमारा हिस्सा लगभग साठ हजार करोड़ रूपए का था, आज जी.एस.टी. एरा में वह हिस्सा लगभग अस्सी हजार करोड़ रूपए का है। बीस हजार करोड़ रूपए की हमारी जो बढ़ोत्तरी हुई है, चूंकि हम एक कंज्यूमर स्टेट हैं, एक हम उपभोक्ता राज्य हैं और इस जी.एस.टी. का जो सर्वाधिक लाभ मिला है वह बिहार जैसे राज्यों को मिला है। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्र की इस महान सरकार को जिसने इस कांतिकारी आर्थिक परिवर्तन किया और हम जैसे बिहार के राज्य में जहां पर हमलोगों ने अब तक के उद्योग-धंधा से हमें एक साजिश के तहत यू.पी.ए. की सरकार ने दूर रखने का काम किया है।

साथियो, सभापति महोदया, मैं बार-बार साथियो कह देता हूँ, उसके लिए मैं माफी चाहूँगा। सभापति महोदया, मैं सबसे अधिक धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय उप मुख्यमंत्री और हमारे वित्त मंत्री सुशील मोदी जी का जिनके बेहतर वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हम इस बात को बड़े फख के साथ कह सकते हैं कि बिहार की जो अर्थ व्यवस्था है, बिहार की जो गति है, बिहार जिस रफ्तार से चल रहा है, हम अपने अन्य पड़ोसी राज्यों से तो लगभग बराबरी पर आ ही चुके हैं, वह दिन दूर नहीं होगा जब आने वाले लगभग दस-पंद्रह सालों में, अगर इस तरह से रफ्तार चलती रही तो हम इस देश के सभी विकसित राज्यों के समकक्ष खड़ा होंगे। सभापति महोदया, मैं इसे चार भाग में

बांटना चाहता हूं और सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का जो सबसे बड़ा कारण है वह है आय का संग्रह करना। हमलोगों ने निरंतर अपने राज्यों की वृद्धि, निरंतर जो हमारा अपना राजस्व है उसकी वृद्धि करते-करते हमलोगों उसे 35 हजार करोड़ तक ले गए हैं। केंद्रीय अनुदान की जो राशि लेनी होती है और उसका जो खर्च करना होता है उसका हमलोगों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है जिसका एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा। केवल आई.ए.डी.एफ. का जो ग्रामीण आधारभूत संरचना कोष के निर्गत होने वाली राशि है उसमें तेइसवें ट्रेंच की जो राशि निर्गत हुई है उसका हमलोगों ने 102 प्रतिशत् उपयोग किया है और आजतक की एक से लेकर 23 में जो ग्रामीण आधारभूत संरचना की राशि जो बिहार में आई है उसका लगभग 70 प्रतिशत् हमलोगों ने उपयोग किया है। यह बेहतर वित्तीय प्रबंधन का एक नमूना है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय सुशील मोदी जी को कि जिस हिसाब से घाटा प्रबंधन का जो एक राजकोषीय घाटा को निरंतर एक सीमा में रखने का काम किया है उसे लगभग हमेशा जी.डी.पी. के तीन प्रतिशत् के अंदर रखने का काम किया है जिसकी सिफारिश वित्त आयोग ने की थी, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। बाकी के कई राज्य उस सिफारिश को मानने में असफल रहे लेकिन हमारे एक बेहतर वित्तीय प्रबंधन ने राजकोषीय घाटा को हमेशा नियंत्रित करने का कार्य किया है। इस कार्य के लिए मैं वित्त मंत्री को और बिहार की सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इनके ऋण प्रबंधन क्षमता को। बिहार सरकार की अर्थ व्यवस्था में जो ऋण प्रबंधन की क्षमता हमलोगों ने हासिल की है, आज तो विपक्षी सदस्य नहीं हैं, अगर ये कहीं सुन रहे होंगे तो मैं इन्हें बताना चाहूंगा कि जब इनकी सरकार थी उस समय जो बिहार के अर्थ व्यवस्था में जो ऋण का बोझ था वह लगभग पचास प्रतिशत् के जी.डी.पी. के आसपास में था, आज हमारी सरकार ने पिछले कई वर्षों से उसे लगभग 25 परसेंट और 30 परसेंट के आसपास में रखने का कार्य किया है। हालांकि कुछ वर्ष पहले यह 32 परसेंट गया था फिर भी हमारी सरकार का यह लगातार प्रयास है कि जो हमारे जी.डी.पी. में और ऋण का जो प्रतिशत् है उसे 25 प्रतिशत् के अंदर में रखने का कार्य किया जाए। यही बात ये सुन नहीं सकते हैं, यही बात ये पढ़ नहीं सकते हैं। इससे इनलोगों को बेचैनी है। और भी कुछ बातों के साथ सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा क्योंकि आज सारे सुनने वाले लोग बैठे हैं और नहीं सुनने वाले, नहीं समझने वाले लोग गए हुए हैं, इसलिए मैं इस बात को बोलना चाहूंगा कि हमलोगों ने, जो हमारा सकल घरेलू उत्पाद है, उसे हम तीन सेक्टर में बांट सकते हैं - प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड्री सेक्टर और थर्ड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में फसल, पशुपालन, मत्स्यपालन इसको ले सकते हैं। इसका योगदान लगभग 25 परसेंट के आसपास है, मुझे इकैकट आंकड़ा याद नहीं है। दूसरा सेक्टर जिसे हम उद्योग का कह सकते हैं उसमें हमारी उपलब्धि कुछ कम है लेकिन तीसरा सेक्टर जो है, सारे

विश्व में जो सेवा का सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, सारे विश्व की अर्थ व्यवस्था, भारत की अर्थ व्यवस्था और साथ-साथ बिहार की अर्थ व्यवस्था में लगभग उसमें 50 प्रतिशत् के आसपास हमारे कुल जी.डी.पी. में इसका योगदान है। इसलिए मैं सरकार से केवल एक आग्रह करना चाहूंगा और एक प्रयास हमलोगों की होनी चाहिए कि हमलोग, जो सेकेंड्री सेक्टर हैं, जो हमारा द्वितीयक सेक्टर है जिसमें हम पूँजीनिवेश के माध्यम से, निजी पूँजी निवेश के माध्यम से और उद्योग के माध्यम से अपने जी.डी.पी. में उसका हिस्सा अगर बढ़ा सके तो शायद बिहार का वह स्वर्णिम काल दूर नहीं रहेगा जिसके हम भागी हैं और जो हमलोग अपने जीवन में लाएंगे। इसलिए मैं यह आग्रह करना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से बिहार के बाहर रहने वाले तमाम लोगों से पूरे विश्व में रहने वाले लोगों से, पूरे भारत में रहने वाले लोगों से कि आप आइए। बिहार में आइए। आप पूँजी निवेश कीजिए। बिहार में उद्योगों का जाल लगाइए। बिहार एक बहुत बड़ा उपभोक्ता राज्य है। हमारे यहां एक करोड़ परिवार है। हमारे यहां दस करोड़ लोग हैं। हमारी जो नित नई, डेली कंज्यूमर गुड्स की जो हमारी जरूरतें हैं, अगर उसका निर्माण हमलोग यहां करने लगें तो हम केवल भारत की ही नहीं, हम विश्व की एक अकेले बड़ी महत्वपूर्ण अर्थ व्यवस्था बन सकते हैं। इसके साथ मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमने अपने बजट को पांच बड़े भागों में बांटा ... क्रमशः

टर्न - 17/कृष्ण/15.02.2019

श्री मनोज कुमार : क्रमशः हमने जो सबसे बड़ा खर्च करने का काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में करने का काम किया। हमने दूसरा जो सबसे बड़ा खर्च करने का काम किया, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में करने का काम किया। हमने तीसरा जो सबसे बड़ा खर्च करने का काम किया, अपने आधारभूत संरचना को मजबूत करने में पथ और ग्रामीण सड़कों को मजबूत करने का काम किया। हमने चौथा जो बड़ा काम किया, सामाजिक कल्याण में राशि देने का काम किया और हमने पांचवां जो बड़ा काम किया, स्वास्थ्य में हमने राशि देने का काम किया। इससे बड़ा एक लोक कल्याणकारी राज्य सरकार का कोई उदाहरण नहीं हो सकता। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सरकार के मुखिया को, सरकार के वित्त मंत्री को, पूरे सरकार के मंत्री को और सरकार को समर्थन करनेवाले तमाम माननीय विधायकों को और मैं सीख देना चाहूंगा विपक्ष को कि बिहार आपका है, इस बिहार के निर्माण की जिम्मेवारी भी आपकी है, हम सब को मिल कर बिहार का निर्माण करना है। हमें अपने जिम्मेवारियों से नहीं भागना है और एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना है, जिसके हित में केवल और केवल बिहार हो। इसलिए आईये, विपक्ष के साथियों, आप भी सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलिये और बिहार का निर्माण कीजिये। महोदया, इस लेखानुदान बजट के समर्थन में मुझे बोलने का समय

दिया, उसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मैंने कम से कम शब्दों में अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री रत्नेश सादा : सभापति महोदया, मैं बिहार विनियोग लेखानुदान के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। विकास की सवारी और सबकी हिस्सेदारी। महोदया, 2005 से लेकर 2019 तक बिहार जो विकास की पटरी पर दौड़ रही है, उसमें सभी वर्ग, सभी जाति, सभी धर्म, युवा हो, वृद्ध हो, नौजवान हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चा हो, सबकी हिस्सेदारी इस बिहार सरकार में 2005 से अभी तक मिली है। महोदया, जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है कि जब बच्चा हॉस्पीटल में जन्म लेता है तो जन्म के समय ही 1400/- रूपया दिया जाता है और जब गांव, ग्राम में वृद्ध व्यक्ति की मृत्यु होती है तो आज हमारे माननीय मुखिया नीतीश कुमार के द्वारा 3000/- रूपया कबीर अन्त्येष्टि के तहत मिलता है। इसलिये विकास की सवारी और सभी वर्गों, सभी जाति और सभी धर्मों की हिस्सेदारी।

महोदया, आज माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार ने और आदरणीय विजेन्द्र बाबू ने एक बहुत बड़ी पहल की है, देश में सबसे बड़ा 10.5 किमी० का पुल भेजा मधेपुर से लेकर बैरिया मंच का निर्माण कराने का काम कर रहे हैं। यह देश का सबसे बड़ा पुल है और हमारे मुखिया ने दीदारगंज में 6 लेन का पुल का निर्माण कराया है। इतना ही नहीं, दीघा घाट में रेल सह सड़क पुल का भी निर्माण कराकर जनता को आने-जाने की सुगम रास्ता की व्यवस्था की है।

महोदया, आज हमारी सरकार ने, मैं जिस कोसी क्षेत्र से आता हूं, वहां 550 करोड़ की लागत से बलुआहा घाट में पुल का निर्माण किया है, जिससे अब सहरसा से दरभंगा की दूरी मात्र 80 किमी० रह गयी है। पहले कोसी के निवासी नरक का जीवन जीते थे। आज उनको माननीय नीतीश कुमार ने स्वर्ग प्रदान कर दिया है। आज विजय घाट में पुल बना करके, मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके, इतना ही नहीं, मिथिला में कोसी महोत्सव का आयोजन करके उग्रतारा महोत्सव करके, खास करके मिथिला सहरसा, मधेपुरा, सुपौल का विकास करने का काम किया है।

महोदया, हमारे माननीय मुखिया ने इसी चलते सत्र में बहुत बड़ा एलान किया है कि जो लोग बी०पी०एल० परिवार से छूटे हुये थे, उन परिवारों को मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के तहत अप्रैल, 2019 से वृद्ध पेंशन मिलेगा।

महोदया, इतना ही नहीं, हमारे पत्रकार बंधु आजादी से लेकर आजतक पत्रकारिता करते आये लेकिन आज 47-48 वर्षों के बीच पत्रकार के सम्मान में कोई मुख्यमंत्री ने अपना नामोनिशान नहीं छोड़ा। लेकिन हमारे माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार ने पत्रकार के सम्मान के लिये 6 हजार पेंशन देने का काम किया और इतना ही नहीं, जब

पत्रकार की असामिक मृत्यु होती है तो उसके परिवार को 3 हजार रूपया देने का एलान किया है।

महोदया, आज नीतीश कुमार जी की देन है कि साल के अंत तक 75 पैसे प्रति यूनिट बिजली किसानों को कृषि हेतु अलग फीडर लगाने का काम कर रही है। भगवान बुद्ध के अस्थि कलश के दर्शन हेतु वैशाली में बुद्ध सम्प्रकाशन संग्रहालय बनेगा। बेतिया, मोतिहारी एवं मुजफ्फरपुर में दो-दो हजार क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण माननीय मुखिया नीतीश कुमार करायेंगे। यह माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा एलान है और सभी प्रमंडलों के जिला मुख्यालयों में 600 क्षमता वाले ऑडिटोरियम का निर्माण कराने का लक्ष्य रखा है माननीय नीतीश कुमार ने।

महोदया, 1 जुलाई, 17 से जी०एस०टी० जो विवादित था, उसका भी निपटारा करने हेतु एनाउंस किया है। माननीय श्री नीतीश कुमार ने 1.5 करोड़ से कम खाता वाले कर दाताओं को खाता अपडेट के मुफ्त सॉफ्ट वेयर की व्यवस्था की है।

महोदया, शिक्षा एवं चिकित्सा ऋण के दस्तावेजों पर देय निबंधन कर घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज में नामांकन जर्झर्इ में स की मेधा सूची के आधार पर कौसिल कर करने का निर्णय लिया गया है।

महोदया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के द्वारा बिहार को सबसे बड़ी सौगात मिलने जा रही है जो कि 17 तारीख को बरौनी में मेट्रो रेल का शिलान्यास करेंगे। यह भारत सरकार की बिहार में सबसे बड़ी उपलब्धि है जो बिहार को सौगात में दे रहे हैं।

महोदया, गया, नवादा, छपरा, भागलपुर, मोतिहारी में भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एम०टेक की पढ़ाई शुरू होगी। इतनाही नहीं, हमारे मुखिया श्री नीतीश कुमार 2005 से गद्दी पर आये हैं तो खास करके महादलितों, पिछड़ा अतिपिछड़ा के लिये जो योजना चलाई है, उसमें खास करके महादलितों के टोला स्वयं सेवक, विकास मित्र को 3 डिसमिल जमीन यहां तक कि राजनीतिक सत्ता में भागीदारी दिलाने के लिये एकल पद पर आरक्षण दे करके मुखिया, सरपंच, समिति, पंचायत समिति, प्रमुख जिला परिषद् के सदस्य बनाकर उनको राजनीतिक सत्ता में उनको भागीदारी दिलाने का काम किया है।

महोदया, आज जो अल्पसंख्यकों के लिये हमारे मुखिया ने साढ़े 8 हजार कब्रिस्तान की घेराबंदी करायी है।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अल्पसंख्यक के सर्टिफिकेट में चाहे वह मौलवी हो, फोकनिया हो, सभी के सर्टिफिकेट को दीमक चाट गया था। लेकिन जब माननीय मुखिया श्री नीतीश कुमार जब आये तो उस दीमक लगे सर्टिफिकेट का लैमिलीशन कराकर आज तालिम-ए-मरकज में बहाली कराया है, मदरसा में बहाली कराया है। इतना ही नहीं, हज कमिटी में अनुदान देने का काम किया है। यह देन है तो बिहार के मुखिया श्री नीतीश

कुमार का देन है। इनका लंबी सोच है जो सभी वर्गों और सभी जाति के लोगों को साथ लेकर चलते हैं।

क्रमशः :

टर्न-18/अंजनी/दि0 15.02.2019

श्री रत्नेश सादा :...क्रमशः..... अध्यक्ष महोदय, सात इंजीनियरिंग कॉलेज, 12 पॉलटेक्निक संस्थान में छात्रों की पढ़ाई शुरू होगी। सड़क शोध संस्थान की स्थापना होगी और इतना ही नहीं, कैंसर और मधुमेह सहित 310 तरह की दवा बिहार सरकार की तरफ से गरीब मरीज और असहाय मरीज को मुफ्त मिलेगी। अररिया, किशनगंज, नालन्दा इंजीनियरिंग कॉलेजों में पढ़ाई शुरू होगी और नालन्दा के रहुई में एक डेंटल कॉलेज का निर्माण होगा। आज नीतीश कुमार जी ने, बिहार में जितने भी बेरोजगार युवक थे, उनको एक हजार रूपया प्रति माह जब तक उनकी नौकरी नहीं हो जाती है, तबतक उनको बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे और यह चल रहा है। लेकिन पूर्व की सरकार ने आजतक बिहार की जनता के बारे में, बिहार के सभी वर्गों के बारे में कभी नहीं सोचने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत चार लाख रूपया देने का काम कर रही है और कन्या विवाह योजना, उत्थान योजना के तहत जन्म से लेकर जबतक उनकी शादी होगी, उसमें भी राशि देने का काम माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी ने किया है। महोदय, सामाजिक सरोकार के तहत समाज के दूषित वातावरण से मुक्ति दिलाने के लिए सर्वप्रथम दलित, महादलित और अतिपिछड़ा के लोग जो दारू के आदी थे, शराब के आदी थे, वे शराब पीने के चलते 25 से 30 वर्षों के अन्दर में ही मर जाते थे, दलित-महादलित को मरने पर केश नहीं पकता था, जो कि दारू पीकर मर जाते थे, बूढ़ा नहीं दिखायी देते थे, उसको बचाने का काम माननीय नीतीश कुमार जी ने किया। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, बाल विवाह, दहेज प्रथा उन्मूलन एवं नशा मुक्ति बिहार बनाने का काम माननीय मुखिया नीतीश कुमार जी ने किया। मैं तो इनको कहता हूँ कि वे युग पुरुष हैं। इन्होंने जो काम किया, आनेवाले हमारे आध्यात्मिक राम थे या कृष्ण थे, कबीर थे या तुलसीदास, सबरी थे कि रविदास थे, उसके अनुकूल आज सभी वर्गों के, सभी धर्मों के, सभी जाति के लोगों को जोड़कर बिहार के विकास के रथ पर सवार होकर आज 12 करोड़ जनता को लेकर चलने का काम किया है। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, लेखानुदान मंग के वाद-विवाद पर सरकार का उत्तर होगा, माननीय मंत्री, वित्त विभाग।

सरकार का उत्तर

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, 12 फरवरी को इस सदन के अन्दर वर्ष 2019-20 का बजट पेश किया गया था। बजट भाषण में मैंने विस्तार से सारी बातों का उल्लेख किया था लेकिन मैं सदन के सामने फिर से इस बात को दुहराना चाहूंगा कि इस साल का जो वर्ष 2019-20 का बजट है, वह 2 लाख 501 करोड़ रूपये का बजट है और हमलोगों को गर्व है कि बिहार जैसे सीमित संसाधनों वाले राज्य ने 2005-06 में जब हमलोगों की सरकार आयी थी, उस समय का बजट था 22,568 करोड़ रूपया, उससे साढ़े नौ गुणा वृद्धि करते हुए हम 2 लाख 501 करोड़ रूपया का आंकड़ा पार कर रहे हैं। महोदय, जो प्लान एक्सपेंडीचर होता है, योजना व्यय, उसमें करीब 20 गुणा की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005-06 में जहां 4898 करोड़ रूपये का प्लान एक्सपेंडीचर था, वह एक लाख करोड़ को पार कर गया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार कहते हैं कि बिहार का विकास विकेन्ड्रित विकास है और अब तो जो आंकड़े हैं, वह यह दर्शाता है, CRISIL की रिपोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया है कि बिहार का विकास रोजगार पैदा करनेवाला विकास है और इस देश में तीन ही राज्य हैं-गुजरात, बिहार और हरियाणा, जिसके बारे में कहा गया कि सर्वाधिक रोजगार पैदा करनेवाला विकेन्ड्रित विकास बिहार ने हासिल किया है। अध्यक्ष महोदय, विकास तो बहुत जगह होता है लेकिन आइलैंड है, कुछ जगह विकास हो गया। इसलिए जो निर्माण का क्षेत्र है, जो मैनुफैक्चरिंग है, जो ट्रेड है, जो ट्रांसपोर्ट है, कम्युनिकेशन, ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां सर्वाधिक रोजगार पैदा होता है। मुझे खुशी है कि हमने केवल 11.3 प्रतिशत के विकास दर को हासिल ही नहीं किया बल्कि सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाले तीन सर्वोच्च राज्यों के अन्दर बिहार भी उसके अन्दर शामिल हुआ है। अध्यक्ष महोदय, तीसरी महत्वपूर्ण बात, महंगाई आम आदमी से जुड़ा मुद्दा है कि किसी राज्य में महंगाई की क्या स्थिति है और उसमें भी मैं सदन को बताना चाहूंगा कि हमने जो विकास हासिल किया है तो कंज्यूमर प्राइस इन्डेक्स जो उपभोक्ता मूल्य सूचनांक होता है, वह अखिल भारतीय 3.6 था, जबकि बिहार में केवल 2.7 था यानी महंगाई दर को भी बिहार में हमलोगों ने नियंत्रित किया है और जहां केरल में महंगाई की दर 6 प्रतिशत थी, तमिलनाडु 4.9 परसेंट, महाराष्ट्र 4.1 परसेंट और 2013 में जितनी महंगाई दर थी, 2013 की तुलना में 2018 में सर्वाधिक गिरावट बिहार, यू०पी० और तेलंगाना के अन्दर महंगाई दर के अन्दर हुई है। अध्यक्ष महोदय, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है, इसलिए केवल विकास दर नहीं, सर्वाधिक रोजगार पैदा करने वाला विकास और महंगाई को नियंत्रित करनेवाला विकास हमलोगों ने देने का काम किया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि पटना के लोगों के लिए, बिहार के लोगों की बड़ी चिर-प्रतिक्षित मांग थी कि पटना के अन्दर मेट्रो आना

चाहिए और हर कदम-कदम पर इसको ट्रैक करते रहे और अंतिम दिन में पी0एम0ओ0 को, जिस भी अधिकारी को फोन करने की आवश्यकता थी, आवश्यक फोन करके पटना मेट्रो स्वीकृत हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और बिहार के मुख्यमंत्री, दोनों को धन्यवाद देना चाहूंगा। जो लोग मजाक उड़ाते हैं कि मेट्रो में 13 हजार करोड़ खर्च हो जायेगा, तो क्या बैलगाड़ी में बिहार के लोग चलते रहें? हुजूर, जब जमाना बुलेट ट्रेन का, मेट्रो ट्रेन का है तो बिहार किसी राज्य से पीछे नहीं रहेगा। जब मुख्यमंत्री गये थे जापान तो पटना से बोध गया के लिए बुलेट ट्रेन जैसी कोई ट्रेन चले, इसकी दिशा में भी काम हो रहा है और 13,268 करोड़ रूपये से दानापुर-मीठापुर और फिर पटना स्टेशन से नया जो आई0एस0बी0टी0 बस अडडा बन रहा है, मुझे खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 17 तारीख को बरैनी में उसका भी शिलान्यास करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, जो लोग बार-बार पैकेज पर सवाल उठाते हैं कि पैकेज का क्या हुआ? अब उनको दिखायी नहीं पड़ता है कि क्या हो रहा पैकेज का। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री के पैकेज में सबसे ज्यादा राशि का प्रावधान किया गया था सड़क प्रक्षेत्र में। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि कुल 74 जो पैकेज थे, उसमें से 74 बहुत योजनायें समावेशित हैं, जिनकी कुल लागत 50,711 करोड़ हैं, इन सभी योजनाओं की लम्बाई 3092 किलोमीटर है और इस पैकेज के 74 में से 5 काम पूरा हो चुका है, 40 पर काम जारी है और 19 काम स्वीकृति की प्रक्रिया में है। इसमें केवल गंगा नदी पर सात पुल बन रहा है, जिसमें महात्मा गांधी सेतु के सामानान्तर नया पुल, पुराने महात्मा गांधी सेतु के पुनरुद्धार का काम, राजेन्द्र पुल के सामानान्तर छः लेन पुल का निर्माण, मुंगेर घाट सड़क-सह-रेल पुल, विक्रमशीला और सबसे सौभाग्य की बात है कि जो भागलपुर के लोग यहां बैठे हुए हैं कि भागलपुर के अन्दर क्या जाम की स्थिति रहती होगी, मुख्यमंत्री जी ने आग्रह किया है नितिन गडकरी जी से और केन्द्र की सरकार ने विक्रमशीला सेतु के सामानान्तर एक नये चार लेन पुल की स्वीकृति हो गयी है। बिहार सरकार जमीन अधिग्रहण का पूरा खर्च जो होगा, 53 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा जमीन अधिग्रहण में, पिछले मंत्रिपरिषद की बैठक में उसकी भी स्वीकृति प्रदान की गयी है। कोसी नदी पर दो नये पुल फुलौत घाट पुल और भेजा घाट पुल, तो अध्यक्ष महोदय, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा लेकिन जो प्रधानमंत्री का पैकेज है, जो सबसे बड़ा हिस्सा था सड़क प्रक्षेत्र का, उसके अन्दर हर योजना पर काम प्रारंभ हो गया है।

...क्रमशः....

टर्न-19/राजेश/15.2.19

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री, क्रमशः: उसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री के पैकेज में करीब 500 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रावधान था पर्यटन के क्षेत्र में और पर्यटन के क्षेत्र में जैन परिपथ, कॉवरिया परिपथ, पटना साहिब गाँधी परिपथ, मंडार एवं अन्य 244 करोड़ की योजना थी, जिसमें से अभी तक 105 करोड़ रुपये बिहार सरकार को प्राप्त होकर और खर्च किया जा रहा है और रामायण परिपथ के लिए 100 करोड़ और बौद्ध परिपथ के लिए 200 करोड़ और इसके अलावा बौद्ध गया कल्चर और सेंटर में भारत सरकार 98 करोड़ दे रही है और शेष राशि बिहार सरकार लगाकर और 145 करोड़ की लागत से एक शानदार ऑडिटोरियम का निर्माण बोध गया में किया जा रहा है, उसी प्रकार बहुउद्घेश्यीय प्रकाश केन्द्र 50 करोड़ की लागत से और पटना साहिब के अंदर भी निर्माणाधीन है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान और मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन का जिक्र किया था। अध्यक्ष महोदय, हमारे संसाधन सीमित हैं लेकिन ऐसी योजनाएँ जो गरीब लोगों को जिससे मदद मिल सके, ऐसी योजनाओं को लेने में बिहार हमारा कभी पीछे नहीं रहा है और मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अभी बिहार के अंदर 43 लाख 78 हजार वृद्ध लोगों को पेंशन मिल रहा है और एक आक्कलन है कि मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में 36 लाख 50 हजार नये वृद्ध जोड़े जायेंगे, तो अगर बिहार के अंदर पहले से चली आ रही योजना और नई योजना इन दोनों को जोड़ लें, तो 80 लाख 28 हजार यानि 80 लाख बूढ़े लोगों को और बिहार सरकार के द्वारा पेंशन मिलेगा और जो लोग मजाक उड़ाते हैं, इतनी राशि, उतनी राशि, अरे बिहार में इतनी गरीबी है कि 400 रुपये के लिए भी लोग दौड़ते रहते हैं और उस गरीब को अगर 400 रुपये भी मिल जाय, तो उसका जीवन गुजर जायेगा। अध्यक्ष महोदय, लगभग मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना में जो हमलोगों को अंदाज है कि लगभग 17052 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय हमको करना पड़ेगा, जो हम पहले से व्यय कर रहे थे उसके अतिरिक्त और कुल मिलाकर बिहार के अंदर एक लाख विधवा, 11 लाख 53 हजार विधवाओं को पेंशन मिल रहा है और सात लाख 17 हजार जो द्विव्यांग है, उनको पेंशन मिल रहा है और इन सभी पेंशन को जोड़ लें और माननीय मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन को भी जोड़ लें तो बिहार के अंदर 1 करोड़ का ऑकड़ा पार कर जायेगा अध्यक्ष महोदय यानि बिहार में 1 करोड़ 55 लाख लोगों को चाहे वह विधवा हो, वृद्धजन हो या द्विव्यांग हो, उनको किसी न किसी पेंशन योजना से हमलोग कभर करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, जब बिहार में बाढ़ आयी थी, तो आपको याद होगा कि 32 लाख से ज्यादा परिवारों के खाते में छः-छः हजार रुपया भिजवाने का काम किया गया था और जब बिहार का किसान आज परेशान था

सूखे के कारण, जब वर्षा नहीं हुई, तो राज्य सरकार ने 24 जिलों के 280 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया और जो संकट में मदद करता है, लोग उसी को याद करते हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि 1430 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया और अभी तक 901 करोड़ रुपया 13 लाख किसानों के खाते में भेजा जा चुका है, डीजल अनुदान में भी 15 लाख 66 हजार किसानों के खाते में 195 करोड़ रुपया ट्रांसफर किया जा चुका है और अध्यक्ष महोदय, यह फसल सहायता योजना के अंदर कोई किसानों को प्रीमियम नहीं देना है और उसके लिए भी बड़ी संख्या में और जो लोग कहते हैं रैयत और गैर रैयत, तो हमारे यहाँ आधे-आधे, गैर रैयत आधे लोगों ने भी उसके लिए आवेदन दिया है और लगभग खरीफ में 11 लाख 50 हजार और रब्बी में अभी तक 11 लाख 24 हजार लोगों का आवेदन प्राप्त हो चुका है और इसके लिए पर्याप्त पैसे की व्यवस्था कर रहे हैं और फसल कटनी के बाद उसमें भी पैसा दे दिया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री किसान योजना के नाम से जो नई योजना आयी है, इसमें छः हजार रुपये प्रति लघु, सीमांत किसानों के खाते में राशि ट्रांसफर किया जायेगा, तो बिहार के किसान कितने जागरुक हैं कि चार दिन या पाँच दिन भी नहीं हुआ है, हमारे पास सुबह तक की रिपोर्ट है कि दो लाख 67 हजार किसानों ने अभी तक अपना निबंधन करा चुका है और बहुत जल्द अध्यक्ष महोदय, इन सभी किसानों के खाते में भी पैसा ट्रांसफर कर दिया जायेगा, तो अध्यक्ष महोदय केवल छः हजार ही नहीं है, यह तो केन्द्र की सरकार छः हजार रुपये दे रही है और वह भी एक साल के लिए नहीं है, जब तक किसान जीवित है, तब तक उसको मिलता रहेगा यानि आजीवन, अगर केन्द्र की सरकार एक साल में 75 हजार करोड़ रुपये खर्च कर रही है, तो आप कल्पना कीजिये कि कितनी बड़ी राशि और होगी। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारा विषय था, चूंकि बजट भाषण में ये सारी बातें आ गयी हैं, मैं उसका जिक्र नहीं करूंगा और अंत में अध्यक्ष महोदय, चूंकि आज शहीदों को हम सब ने नमन किया है और सदन ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, तो मैं भी एक कविता के माध्यम से उन शहीदों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और सदन से आग्रह करूंगा कि इस लेखानुदान को पारित करेंगे:

मेरा देश मेरी जान है, मेरा गर्व है अभिमान,
और यह अभिमान है जिंदा क्योंकि सीमा पर वीर जवान है,
जल हो जमीन हो या आसमान कभी झुके नहीं भारत की शान,
मेरे देश के जवान तुझको शत-शत प्रणाम, मेरे देश के जवान तुझको शत-शत
प्रणाम ।

अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं उन वीर शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और मैं सदन से चाहूंगा कि इस लेखानुदान को पारित करें ।

अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, लेखानुदान मांग पर चौंकि कोई संशोधन प्रस्ताव मूव नहीं हुआ है, इसलिए अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूँ।

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

“लेखानुदान वर्ष 2019-20 की अनुसूची के स्तंभ 8 से 11 में अंकित अधिक से अधिक 77338,52,96,000 (सतहत्तर हजार तीन सौ अड़तीस करोड़, बावन लाख, छियानवे हजार) रूपये मात्र की रकम का लेखानुदान उक्त अनुसूची के स्तंभ में प्रवृष्ट अनुसार मांग शीर्षक के संबंध में 31 मार्च, 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर खर्च करने के लिए स्वीकृत किया जाय।”

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

मांग स्वीकृत हुई।

माननीय सदस्यगण, अब विधायी कार्य।

विधायी कार्य

राजकीय (वित्तीय) विधेयक

“बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019”

अध्यक्षः प्रभारी मंत्री, वित्त विभाग।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

“बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

पुरःस्थापित करने की अनुमति दी गई।

प्रभारी मंत्री।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : मैं इसे पुरःस्थापित करता हूँ।

अध्यक्षः यह पुरःस्थापित हुआ।

विचार का प्रस्ताव। प्रभारी मंत्री।

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 पर विचार हो।”

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“बिहार विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2019 पर विचार हो ।”
विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अब मैं खण्डशः लेता हूँ ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खण्ड-2 एवं 3 इस विधेयक का अंग बने ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“अनुसूची इस विधेयक का अंग बने ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
अनुसूची इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

“नाम इस विधेयक का अंग बने ।”
प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
नाम इस विधेयक का अंग बना ।

टर्न-20/सत्येन्द्र/

स्वीकृति का प्रस्ताव

श्री सुशील कुमार मोदी, उप मुख्यमंत्री: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

“ बिहार विनियोग(लेखानुदान)विधेयक, 2019 स्वीकृत हो ।”

अध्यक्षः प्रश्न यह है कि

“ बिहार विनियोग(लेखानुदान)विधेयक, 2019 स्वीकृत हो । ”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । बिहार विनियोग(लेखानुदान)विधेयक, 2019 स्वीकृत हुआ ।

माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 15 फरवरी, 2019 के लिए स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या 46 है । अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

माननीय सदस्यगण, महामहिम के यहां से एक सूचना दी गयी है कि आज जो वहां अल्पाहार का कार्यक्रम आयोजित था कश्मीर में हुए आतंकवादी घटना के परिप्रेक्ष्य में उसे स्थगित कर दिया गया है ।

अब सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 18 फरवरी, 2019 को 11 बजे पूर्वांतर के लिए स्थगित की जाती है ।

(सभा की बैठक 5.03 बजे अपराह्न में स्थगित हुई)